नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 014
दि. 14.10.2025,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : JIGNESHKUMAR PETHABHAI VAGHELA Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

EPFO का बड़ा फैसला: अब 100% PF निकासी की अनुमति, शिक्षा और शादी के लिए 15 बार तक निकाल सकेंगे पैसा, डॉक्यूमेंट्स जमा करने की झंझट खत्म

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश के करोड़ों नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने नियमों को बेहद आसान बना दिया है। अब कर्मचारियों को अपने EPF अकाउंट से पूरा पैसा निकालने की सुविधा मिल जाएगी। सोमवार, 13 अक्टूबर को हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की बैठक में यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने की।

पहले EPF से पैसा निकालना एक लंबी और पेचीदा प्रक्रिया थी। 13 तरह के नियमों और ढेर सारे दस्तावेजों की जरूरत होती थी। लेकिन अब EPFO ने उन सभी पुराने नियमों को खत्म कर केवल तीन सरल श्रेणियों में बांट दिया है — आवश्यक जरूरतें (बीमारी, शिक्षा, शादी), हाउसिंग जरूरतें (मकान निर्माण, मरम्मत, लोन आदि) और विशेष परिस्थितियां (प्राकृतिक आपदा, महामारी, बेरोजगारी)।

सबसे बड़ी राहत यह है कि अब सदस्य अपने खाते में जमा कुल राशि (कर्मचारी और नियोक्ता दोनों हिस्सों समेत) को निकाल सकते हैं। पहले शिक्षा और शादी के लिए केवल तीन बार निकासी की अनुमति थी, लेकिन अब शिक्षा के लिए 10 बार और शादी के लिए 5 बार तक निकासी की जा सकेगी। इसके साथ ही, न्यूनतम सेवा अवधि को घटाकर सिर्फ 12 महीने कर दिया गया है, जिससे नए जॉइनर्स को भी जल्दी फायदा मिल सकेगा।

पहले किसी विशेष परिस्थिति में पैसा निकालने के लिए कारण बताना जरूरी होता था। जैसे – महामारी, लॉकडाउन या नौकरी छूटने जैसी स्थिति में कारणों का प्रमाण देना पड़ता था। अब यह झंझट खत्म कर दी गई है। कर्मचारी अब बिना किसी कारण बताए विशेष परिस्थितियों में भी पैसा निकाल सकेंगे।

हालांकि EPFO ने यह सुनिश्चित किया है कि खाताधारक अपने भविष्य के लिए कुछ रकम बचाए रखें। इसके तहत खाते में कम से कम 25% राशि मिनिमम बैलेंस के रूप में बनी रहनी चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि खाताधारक को 8.25% ब्याज दर और कंपाउंड इंटरेस्ट (चक्रवृद्धि ब्याज) का लाभ लगातार मिलता रहे।

सबसे दिलचस्प बदलाव ऑटो-सेटलमेंट प्रोसेस में किया गया है। अब किसी भी प्रकार के दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी। सिस्टम को पूरी तरह ऑटोमैटिक बनाया जा रहा है, जिससे निकासी का पैसा सीधे बैंक खाते में कुछ ही दिनों में ट्रांसफर हो जाएगा। पहले फाइनल सेटलमेंट में 2 महीने तक का समय लगता था, अब यह अवधि 12 महीने तक बढ़ा दी गई है ताकि सदस्य अपनी सुविधानुसार निर्णय ले सकें। वहीं पेंशन निकासी की अवधि को भी 2 महीने से बढ़ाकर 36 महीने कर दिया गया है।

EPFO ने साथ ही एक नई पहल शुरू की है — 'विश्वास योजना', जिसके तहत देर से PF जमा करने वालों को भारी राहत मिलेगी। पहले जुर्माने की दर काफी अधिक थी, लेकिन अब इसे घटाकर सिर्फ 1% प्रति माह कर दिया गया है। अगर जमा में देरी 2 महीने तक है तो केवल 0.25%, और 4 महीने तक है तो 0.50% का जुर्माना लगेगा। यह योजना फिलहाल 6 महीने तक चलेगी और जरूरत पड़ने पर इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है।

पेंशनर्स के लिए भी बड़ी खबर है। EPFO ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के साथ समझौता किया है, जिससे अब EPS-95 पेंशनर्स घर बैठे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) जमा कर सकेंगे। यह सुविधा पूरी तरह मुफ्त होगी और इसका खर्च (50 प्रति सर्टिफिकेट) EPFO खुद उठाएगा। इससे दूरदराज़ और ग्रामीण इलाकों के बुजुर्ग पेंशनर्स को बहुत राहत मिलेगी।

डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में EPFO ने एक नया फ्रेमवर्क भी शुरू किया है — EPFO 3.0, जिसमें क्लाउड-बेस्ड टेक्नोलॉजी, मोबाइल ऐप, और ऑटो-क्लेम सेटलमेंट की आधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी। इससे देशभर के 30 करोड़ से ज्यादा खाताधारकों को तेज, पारदर्शी और परेशानी-रहित सेवाएं मिलेंगी।

फंड मैनेजमेंट के लिए भी सुधार किए गए हैं। EPFO ने अपने डेट पोर्टफोलियो को संभालने के लिए चार नए फंड मैनेजर नियुक्त किए हैं, जो अगले पांच साल तक फंड्स को सुरक्षित और विविध रूप में निवेश करेंगे, ताकि खाताधारकों को बेहतर और स्थिर रिटर्न मिल सके।

यह फैसला देश के संगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों लोगों के लिए एक बड़ी राहत और आज़ादी का प्रतीक माना जा रहा है। अब वे अपने जीवन की जरूरतों — चाहे बच्चों की शिक्षा हो, शादी का खर्च हो या मकान का सपना — सब कुछ अपने ही पसीने के पैसे से, बिना किसी झंझट के पूरा कर सकेंगे।

आईआरसीटीसी घोटाला: लालू, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ आरोप तय, अदालत में होगी औपचारिक सुनवाई

(जीएनएस)। नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में पर्याप्त सबूत हैं और अब मुकदमे की औपचारिक सुनवाई शुरू होगी। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि लालू यादव ने लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया और टेंडर प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर अनियमितता को बढ़ावा दिया, जिससे कुछ खास लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए षड्यंत्र रचा गया।

कोर्ट के अनुसार, आईआरसीटीसी के होटलों के रखरखाव से जुड़े टेंडर में जानबूझकर शर्तों में बदलाव किया गया ताकि लाभ कुछ विशेष लोगों को मिले। इस प्रक्रिया में सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा। अदालत ने कहा कि लालू यादव ने कोचर परिवार से कम कीमत पर जमीन खरीदने की साजिश रची और बाद में इन जमीनों का नियंत्रण राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को हस्तांतरित करने के लिए मिलीभगत की गई। अदालत ने तीनों नेताओं से पूछा कि क्या वे आरोप स्वीकार करते हैं, जिस पर सभी ने खुद को बेगुनाह बताया और आरोपों को निराधार कहा।

सीबीआई ने अदालत में प्रस्तुत किए सबूत

सीबीआई ने कई दस्तावेज और गवाहों के बयान अदालत में पेश किए, जिनसे साबित होता है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने टेंडर प्रक्रिया को प्रभावित किया। अदालत ने कहा कि ये सबूत आरोप तय करने के लिए पर्याप्त हैं।

मुकदमे की धाराएं

अदालत ने आदेश दिया कि लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), 120B (षड्यंत्र) और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2) के तहत मुकदमा चलेगा। भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2) के तहत दोषी पाए जाने पर न्यूनतम एक वर्ष और अधिकतम सात वर्ष की सजा का प्रावधान है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

मामले का समय और संदर्भ

यह मामला लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते 2004 से 2009 के बीच का है। आरोप है कि उन्होंने आईआरसीटीसी के रांची और पुरी के होटलों के रखरखाव के ठेकों में भ्रष्टाचार किया और इन्हें अपनी पत्नी की कंपनी को अनुचित रूप से दिलवाया। सीबीआई के अनुसार, इन होटलों के ठेके राबड़ी देवी की कंपनी सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए, जिसके बदले कंपनी ने लालू परिवार को आर्थिक लाभ पहुंचाया।

सीबीआई ने अपने आरोपपत्र में कहा कि 2004 से 2014 के बीच एक सुनियोजित साजिश के तहत आईआरसीटीसी के होटलों को सुजाता होटल्स को पट्टे पर देने की प्रक्रिया तय की गई और निविदा शर्तों में जानबूझकर हेराफेरी की गई ताकि लालू परिवार को फायदा हो।

अन्य आरोपी और कंपनियां

इस मामले में आईआरसीटीसी के पूर्व अधिकारी वी.के. अस्थाना, आर.के. गोयल, सुजाता होटल्स के निदेशक विजय और विनय कोचर सहित कुल 14 आरोपी हैं। इसके अलावा, डिलाइट मार्केटिंग कंपनी (अब लारा प्रोजेक्ट्स) और सुजाता होटल्स को भी आरोपी कंपनियों के रूप में नामित किया गया है। यह फैसला लालू परिवार के लिए एक गंभीर चुनौती है और अब अदालत में औपचारिक मुकदमे की सुनवाई के दौरान सबूत और गवाहों के आधार पर केस की गहराई से जांच होगी।

पाकिस्तान में टीएलपी प्रदर्शन हिंसक, पांच की मौत और कई घायल

(जीएनएस)। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सोमवार को कट्टरपंथी इस्लामी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) के सदस्यों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें कम से कम पांच लोग मारे गए। इस घटना में एक पुलिसकर्मी समेत चार प्रदर्शनकारी भी शामिल हैं, जबकि कई पुलिस अधिकारी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने कहा कि हिंसा का सिलसिला उस समय शुरू हुआ जब टीएलपी के हजारों सदस्य लाहौर से विरोध मार्च करते हुए इस्लामाबाद की ओर बढ़े और अमेरिकी दूतावास तक पहुंचने का प्रयास किया। टीएलपी ने यह विरोध मार्च गाजा के लोगों के समर्थन में किया। हालांकि, गाजा में युद्ध समाप्त हो चुका था और वहां शांति बहाल हो गई थी। बावजूद इसके, संगठन ने अपने विरोध प्रदर्शन को जारी रखने का निर्णय लिया। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा कर्मियों के साथ टकराव किया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पुलिस ने विरोधकारियों को तितर-बितर करने और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस और लाठियां भी इस्तेमाल की। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बलों ने स्थिति पर काबू पाने के लिए विशेष प्रबंध किए। हालांकि, हिंसक झड़पों में कई प्रदर्शनकारी घायल हुए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस क्षेत्र से दूर रहें और स्थिति सामान्य होने तक बाहर न निकलें। यह घटना टीएलपी के बढ़ते विरोध और कट्टरपंथी गतिविधियों को लेकर पाकिस्तान में सुरक्षा चुनौतियों को भी उजागर करती है। देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच अक्सर झड़पें होती रहती हैं, और इस बार की हिंसा ने प्रशासन के लिए चेतावनी का संकेत दिया है कि ऐसे समूहों के प्रदर्शन को शांतिपूर्ण तरीके से नियंत्रित करना आवश्यक है। स्थानीय मीडिया के अनुसार, प्रशासन ने पहले ही इस्लामाबाद और लाहौर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों की भारी संख्या और उग्र रवैये ने हिंसा को रोकना मुश्किल बना दिया।

गुजरात में 31 अक्तूबर को करेंगे महापंचायत, आप का किसानों के समर्थन में विरोध

(जीएनएस)। नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने गुजरात सरकार पर किसानों के खिलाफ दमन की कार्रवाई करने का आरोप लगाया है और इस विरोध में 31 अक्तूबर को गुजरात में महापंचायत आयोजित करने की घोषणा की है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल इस महापंचायत में शामिल होंगे।

आप के गुजरात प्रभारी गोपाल राय ने सोमवार को दिल्ली स्थित मुख्यालय में प्रेसवार्ता कर कहा कि बीते रविवार को भावनगर जिले के बोटाद विधानसभा क्षेत्र के हडधड़ गांव में पंचायत कर रहे किसानों पर राज्य सरकार के इशारे पर लाठी-डंडे बरसाए गए। राय ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार किसानों के साथ अन्याय और दमन की नीति अपना रही है। उन्होंने बताया कि इस घटना के विरोध में सोमवार को आप ने पूरे गुजरात में किसानों के समर्थन में काला दिवस मनाया। इस दौरान आप के नेता और किसान नेता मिलकर हर मंडी में जनसुनवाई करेंगे और किसानों के दुख-दर्द को सुनेंगे। गोपाल राय ने कहा कि 31 अक्तूबर को आयोजित महापंचायत में किसानों की आवाज को मजबूती मिलेगी और सरकार को उनके अधिकारों और मांगों का ध्यान देने के लिए मजबूर किया जाएगा।

पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार किसानों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेती है तो आंदोलन और विरोध की गति और तेज होगी। केजरीवाल ने इस महापंचायत को किसानों के हक और न्याय की लड़ाई के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसमें पूरे राज्य से किसान और आप के कार्यकर्ता शामिल होंगे।

मणिपुर में सुरक्षा बलों ने दो उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार और बारूद बरामद

(जीएनएस)। इंफाल। मणिपुर में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में दो उग्रवादी गिरफ्तार किए गए हैं, साथ ही बिष्णुपुर जिले से भारी मात्रा में हथियार और बारूद भी जब्त किया गया है। पुलिस के मुताबिक, ये गिरफ्तारी और बरामदगी रविवार को विभिन्न अभियानों के दौरान की गई। सुरक्षा बलों ने बताया कि बिष्णुपुर जिले में अलग-अलग अभियान चलाकर 12 आग्नेयास्त्र बरामद किए गए। वहीं, इंफाल ईस्ट और वेस्ट जिलों में प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े दो उग्रवादी पकड़ में आए। विशेष रूप से, इंफाल वेस्ट जिले के लामशांग हाओरंग सबल में एक सक्रिय उग्रवादी को उसके आवास से गिरफ्तार किया गया। इसकी पहचान 22 वर्षीय कोंथौजम विकास मैतेई के रूप में हुई, जो प्रतिबंधित संगठन कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (पीएसपी) का सक्रिय सदस्य बताया गया है।

पुलिस ने कहा कि गिरफ्तारियों और बरामदगी से इलाके में सुरक्षा बढ़ाने में मदद मिलेगी और प्रतिबंधित संगठनों की गतिविधियों पर नियंत्रण सुनिश्चित होगा। इस कार्रवाई के बाद मणिपुर के अन्य जिलों में भी सुरक्षा बल सतर्क हैं और संदिग्ध गतिविधियों की लगातार निगरानी कर रहे हैं। सुरक्षा बलों ने आम जनता से भी अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध जानकारी को पुलिस के साथ साझा करें, ताकि राज्य में शांति और सुरक्षा बनाए रखी जा सके।

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की एसआईटी जांच की मांग खारिज की, निर्वाचन आयोग को किया जिम्मेदार

(जीएनएस)। नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने की याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की पीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका नहीं है और उपयुक्त प्राधिकरण केवल निर्वाचन आयोग ही है। पीठ ने यह भी सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता अपनी शिकायत सीधे आयोग के पास दर्ज करा सकते हैं। याचिका में बेंगलुरु सेंट्रल और अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी का हवाला देते हुए पूर्व जज की अध्यक्षता में एसआईटी गठित करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने यह भी आग्रह किया कि जब तक स्वतंत्र ऑडिट पूरी तरह से न हो, मतदाता सूची में कोई संशोधन या अंतिम रूप न दिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया और कहा कि इस चरण पर वह मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं करेगी। अधिवक्ता रोहित पांडेय ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता पहले ही निर्वाचन आयोग को प्रतिवेदन सौंप चुके हैं, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए किसी समयसीमा का निर्धारण करने से भी इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से स्पष्ट हो गया कि मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी की शिकायतों की जांच के लिए केवल निर्वाचन आयोग ही जिम्मेदार प्राधिकरण है।

गुजरात में मानसून की तबाही: 70 सालों में 15,000 करोड़ का नुकसान और हजारों मौतें

(जीएनएस)। गुजरात में हर साल मानसून के दौरान बाढ़ और भारी बारिश से औसतन 175 लोगों की मौत होती है। 1953 से 2022 तक राज्य में मानसूनी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है, जिससे हजारों करोड़ रुपये की संपत्ति, फसलें और सार्वजनिक ढांचे बर्बाद हुए। पिछले पांच सालों में देशभर में बाढ़ से 9,111 लोगों की मौत और लगभग 2.13 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ, जिससे करोड़ों लोग प्रभावित हुए।

इस साल भी देश के कई राज्यों में मानसून आफत बनकर बरसा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ ने व्यापक तबाही मचाई। गुजरात के लिए सेंट्रल वाटर कमीशन (CWC) की 'रिपोर्ट ऑन फ्लड डैमेज स्टेटिस्टिक्स' में सामने आया है कि 1953 से 2022 तक राज्य को बाढ़ और बारिश से भारी नुकसान हुआ।

गुजरात में बाढ़ का आर्थिक और मानव जीवन पर प्रभाव

रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 70 वर्षों में गुजरात में लगभग 10 हजार लोगों की मौत बाढ़ के कारण हुई। 1953 से 2022 तक फसल नुकसान का आंकड़ा 25,474 करोड़ रुपये, घरों का नुकसान 4,701 करोड़ रुपये, और मारे गए जानवरों की संख्या 7.34 लाख रही। कुल मिलाकर राज्य को इस अवधि में लगभग 15,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

पिछले पांच वर्षों में हर साल लगभग 47 लाख लोग भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित हुए। किसानों की फसलें बर्बाद हुईं और लगभग 7.20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की फसल को नुकसान हुआ, जिससे सालाना लगभग 580 करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ। इस दौरान हर साल औसतन 12,000 जानवरों की मौत हुई।

सबसे बड़ा नुकसान और प्रभावित क्षेत्र

गुजरात में सबसे ज्यादा नुकसान साल 2017 में हुआ, जब 3,500 करोड़ रुपये का नुकसान दर्ज किया गया। 2018 से 2022 के बीच राज्य में 5,753 करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ।

देशभर में बाढ़ की तुलना करें तो राजस्थान को 26,271 करोड़, तमिलनाडु को 27,041 करोड़, कर्नाटक को 26,596 करोड़, पश्चिम बंगाल को 17,407 करोड़, केरल को 12,577 करोड़, आंध्र प्रदेश को 11,703 करोड़, असम को 11,513 करोड़, महाराष्ट्र को 10,526 करोड़, और बिहार को 7,261 करोड़ का नुकसान हुआ।

राष्ट्रीय स्तर पर बाढ़ का प्रभाव

2018 से 2022 के बीच देशभर में हर साल औसतन 3.5 करोड़ लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। इस दौरान 3 करोड़ हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र की फसलें नष्ट हुईं, जिनकी कुल लागत 67,000 करोड़ रुपये रही। लगभग 26.47 लाख घरों को 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ और सार्वजनिक संपत्ति को 53,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। कुल मिलाकर पिछले पांच सालों में देश में बाढ़ और भारी बारिश से हुए आर्थिक नुकसान का आंकड़ा लगभग 21.31 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। गुजरात और अन्य प्रभावित राज्यों में मानसून की यह तबाही साफ दर्शाती है कि बाढ़ और भारी बारिश से होने वाले मानव जीवन, कृषि और आर्थिक नुकसान को रोकने के लिए समन्वित और प्रभावी नीतियों की आवश्यकता है।

संपादकीय

बड़े उद्योगों की जवाबदेही

लगातार ग्लोबल वार्मिंग संकट से जूझती दुनिया में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पर नियंत्रण की दिशा में भारत सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता जतायी है। केंद्र सरकार के गत सप्ताह की शुरुआत में अधिसूचित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम, भारत में औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षरण रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम कहा जा रहा है। इन नियमों ने कार्बन-प्रधान उद्योगों के लिये देश के पहले कानूनी रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन न्यूनतम करने के लक्ष्य निर्धारित किए हैं। ऐसे में, जो उत्पादन इकाइयां अपने निर्धारित लक्ष्य से कम कार्बन का उत्सर्जन करती हैं, वे व्यापार योग्य कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकती हैं। वहीं दूसरी ओर निर्धारित लक्ष्य से अधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाली इकाइयों को भारतीय कार्बन बाजार से समतुल्य क्रेडिट खरीदना होगा या फिर जुर्माना देने को बाध्य होना होगा। दरअसल, एल्युमीनियम, सीमेंट, लुगदी एवं कागज आदि क्षेत्रों की 282 औद्योगिक इकाइयों को 2023-24 के आधार रेखा स्तर से अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि पहले अनुपालन चक्र में कुछ बड़ी कंपनियां शामिल हैं, जिसमें वेदांता, हिंडाल्को, नाल्को और बाल्को द्वारा संचालित एल्युमीनियम स्मेल्टर और अल्ट्राटेक, डालमिया, जे.के सीमेंटे,श्री सीमेंट और एसीसी के स्वामित्व वाले बड़े सीमेंट संयत्र शामिल हैं। निश्चित रूप से केंद्र सरकार ने एक सख्त संदेश दिया है कि बड़े औद्योगिक घरानों को हरित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये अनुकरणीय उदाहरण पेश करना होगा। यदि ये ताकतवर बड़े घराने हरित लक्ष्यों की पूर्ति के लिये सार्थक पहल करते हैं तो आम लोगों को भी उससे प्रेरणा मिलेगी। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक देश है। जिसमें चीन पहले और अमेरिका दूसरे स्थान पर है। निस्संदेह, नये नियम, जो उद्योगों को उत्सर्जन कम करने के लिये प्रोत्सहित करते हैं, उनके औद्योगिक प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार ऊर्जा दक्षता योजना पर आधारित हैं। जिसने ऊर्जा-बचत के लक्ष्य निर्धारित किए। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसे दंड लगाने और समयबद्ध निगरानी व वसूली का काम सौंपा गया है, को कानूनी ढांचे के अनुसार सख्ती से कार्य करने की आवश्यकता है। इस बाबत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को बड़े औद्योगिक दिग्गजों के प्रतिरोध के लिये पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। यह बात उत्साहजनक है कि भारत ने इस वर्ष पहली छमाही में पहले से कहीं अधिक सौर और पवन ऊर्जा का उत्पादन किया। जबकि इस अवधि के दौरान भारत के बिजली क्षेत्र में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में साल-दर-साल आधार पर एक प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। मानवीय गतिविधियों से निकलने वाली ग्रीनहाउस गैसों को जलवायु परिवर्तन का सबसे अहम कारक माना जाता है। हमारा देश, जिसने इस वर्ष ही जलवायु प्रभाव संबंधी आपदाओं की बाढ़ देखी है, को स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये युद्ध स्तर पर प्रयास करना चाहिए। निस्संदेह, सतत विकास - जलवायु के प्रति संवेदनशीलता कार्बन-तटस्थ भविष्य की ओर बढ़ने के अनुरूप होना चाहिए।

Rare Earths को लेकर China का रोज रोज का झँझट खत्म करने की तैयारी में हैं

> भारत सरकार दो महीने का रेयर अर्थ भंडार तैयार करने की योजना बना रही है, जिसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह कार्यक्रम "नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन" (NCMM) के अंतर्गत शुरू होगा, जिसके तहत पहले से ही 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

वैश्विक रणनीति और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा के इस युग में "रेयर अर्थ एलिमेंट्स" केवल वैज्ञानिक तत्व नहीं रहे बिल्क् ये अब भू-राजनीतिक शक्ति का स्रोत बन चुके हैं। चीन द्वारा रेयर अर्थ मैग्नेट के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों ने न केवल अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं में हलचल मचा दी है, बल्कि भारत सहित विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को अपनी रणनीतियाँ पुनः परिभाषित करने पर मजबूर कर दिया है। इसी पृष्ठभूमि में भारत सरकार अब नेशनल क्रिटिकल मिनरल स्टॉकपाइल (NCMS) कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी में है जो आने वाले वर्षों में भारत की तकनीकी और सामरिक आत्मनिर्भरता का आधार स्तंभ बन सकता है। हम आपको बता दें कि रेयर अर्थ तत्व कुल 17 विशिष्ट धात्विक तत्वों का समूह हैं, जिनमें नियोडिमियम, प्रसीओडिमियम, डिसप्रोसियम आदि शामिल हैं। इन तत्वों की खासियत यह है कि ये आधुनिक प्रौद्योगिकी की लगभग हर अहम मशीनरी में काम आते हैं— इलेक्ट्रिक वाहनों के मोटर, पवन चक्कियों के टर्बाइन, मोबाइल फोन, मिसाइलों के गाइडेंस सिस्टम और यहां तक कि उपग्रहों के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी।

इसे भी पढ़ें: भारत पर लगाई शर्तें और अमेरिका को दिया जवाब, रेयर अर्थ के जरिये चीन ने चली नई सामरिक चाल

इनकी मांग तेजी से बढ़ रही है, लेकिन विश्व आपूर्ति का लगभग 85% हिस्सा अभी भी चीन नियंत्रित करता है। जब चीन निर्यात पर रोक लगाता है, तो वैश्विक उद्योगों की नींव डगमगा जाती है। ऐसे में भारत की यह पहल केवल औद्योगिक नीति नहीं, बल्कि सामरिक आवश्यकता भी है। हम आपको बता दें कि भारत सरकार अब दो महीने का रेयर अर्थ भंडार तैयार करने की योजना बना रही है, जिसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह कार्यक्रम "नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन" (NCMM) के अंतर्गत शुरू होगा, जिसके तहत पहले से ही 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस पहल का पहला लक्ष्य रेयर अर्थ तत्वों की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना है, ताकि देश में रेयर अर्थ मैग्नेट उत्पादन को गति मिल सके। इसके लिए सरकार ने पहले ही 7,300 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन कार्यक्रम को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य अगले पांच वर्षों में 6,000 टन उत्पादन हासिल करना है।

सरकार का इरादा भविष्य में इस दायरे को अन्य महत्वपूर्ण खनिजों— जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकल और ग्रेफाइट तक विस्तारित करने का भी है। हम आपको बता दें कि भारत में रेयर अर्थ की उपलब्धता का अनुमान लगभग 7.23 मिलियन टन रेयर अर्थ ऑक्साइड का है, जो मुख्यतः 13.15 मिलियन टन मोनाजाइट अयस्क में पाया जाता है। ये अयस्क आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में फैले हुए हैं। हालांकि, असली चुनौती इन तत्वों को निकालने और शुद्ध करने की तकनीकी क्षमता की है। वर्तमान में भारत अपने घरेलू भंडारों से इन तत्वों का सीमित उपयोग करता है और प्रोसेसिंग के लिए बड़े पैमाने पर चीन और अन्य देशों पर निर्भर है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को यदि वास्तविक आत्मनिर्भरता हासिल करनी है, तो केवल भंडारण नहीं, बल्कि प्रसंस्करण और परिष्करण तकनीकों में निवेश करना होगा। देखा जाये तो चीन के कदम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि "खनिज कूटनीति" आने वाले दशकों में ऊर्जा और रक्षा नीति का नया मोर्चा बनेगी। अमेरिका ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और चीनी आयात पर 100% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। भारत के लिए यह अवसर और चुनौती दोनों है। यदि भारत समय रहते अपनी तकनीकी क्षमता विकसित कर लेता है और वैकल्पिक आपूर्ति स्रोतों— जैसे ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, ब्राज़ील या अफ्रीकी देशों से साझेदारी करता है, तो वह न केवल अपनी घरेलू जरूरतें पूरी कर सकेगा बल्कि एशिया में एक सप्लाई हब के रूप में उभर सकता है। हम आपको बता दें कि खनिज मंत्रालय ने अब तक पाँच चरणों में 55 रणनीतिक और महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी की है, जिनमें से 34 सफलतापूर्वक आवंटित किए जा चुके हैं। छठा चरण हाल ही में आरंभ हुआ है। यह निरंतरता दर्शाती है कि भारत अब खनिज नीति को केवल संसाधन-शोधन तक सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और औद्योगिक नीति के साथ जोड़ रहा है। हम आपको बता दें कि रेयर अर्थ केवल 'भू-संसाधन' नहीं हैं बल्कि ये भारत के मेक इन इंडिया और ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन की आत्मा हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों, सौर ऊर्जा, और रक्षा उपकरणों के लिए ये तत्व उतने ही जरूरी हैं जितना तेल किसी अर्थव्यवस्था के लिए। देखा जाये तो भारत का यह कदम समयोचित और दूरदर्शी है। जब चीन जैसी ताकतें आपूर्ति को कूटनीतिक हथियार बना रही हैं, तब भारत अपनी स्वतंत्र आपूर्ति व्यवस्था और भंडारण नीति के माध्यम से "सप्लाई सिक्योरिटी" का मजबूत ढांचा तैयार कर रहा है। फिलहाल मात्र दो महीने का भंडार और सीमित क्षमता एक शुरुआत है, लेकिन दिशा स्पष्ट है। यह उस भारत की झलक है जो हर संकट को अवसर में बदलना जानता है। रेयर अर्थ के इस दौर में भारत ने संदेश दिया है- "खनिज भी अब रणनीति हैं और आत्मनिर्भरता ही सर्वोच्च कूटनीति है।"

प्रेरणा

हाजिरजवाबी की दिव्य शक्तिः एक किसान ने कैसे अपनी बुद्धि से दोनों देवियों को प्रसन्न कर लिया

बहुत समय पहले की बात है। त्रिलोक में एक बार बड़ा ही विचित्र प्रसंग उत्पन्न हुआ। स्वर्गलोक में देवी लक्ष्मी और देवी दरिद्रता के बीच एक दिन सुंदरता को लेकर तीव्र विवाद छिड़ गया। लक्ष्मी जी, जो संपन्नता, वैभव और सौभाग्य की अधिष्ठात्री हैं, गर्वपूर्वक बोलीं—"मुझसे सुंदर कौन हो सकता है? जहाँ मैं जाती हूँ, वहाँ हर वस्तु स्वर्णवत् चमक उठती है, हर मनुष्य का मुख आनंद से खिल जाता है। मेरे आगमन से घर में प्रकाश, संगीत और मधुरता फैल जाती है। मैं ही सौंदर्य का सच्चा प्रतीक हूँ।"

यह सुनकर दरिद्रता देवी ने उत्तर दिया—"हे लक्ष्मी, तुम्हारा सौंदर्य केवल तब तक टिकता है जब तक तुम किसी के घर में ठहरती हो। लेकिन जब मैं उस घर में जाती हूँ, तो वही रूप, वही ऐश्वर्य, वही गर्व सब मिट जाता है। मेरा सौंदर्य भय और विषाद में नहीं, बल्कि परिवर्तन की गहराई में छिपा है। जब मैं जाती हूँ, तो हर प्राणी विनम्र बन जाता है, अहंकार झुक जाता है। इसीलिए मेरे रूप को नकारा नहीं जा सकता। मैं भी उतनी ही प्रभावशाली हूँ जितनी तुम।"

दोनों देवियाँ अपनी-अपनी महत्ता सिद्ध करने में अड़ी रहीं। देवगण भी इस वाद-विवाद को देखकर मौन थे, क्योंकि कोई भी देवी लक्ष्मी के विपरीत कुछ कहने का साहस नहीं कर सकता था, और दरिद्रता देवी को भी तिरस्कृत करना अनुचित था, क्योंकि उसके भय से ही मनुष्य परिश्रम और विनम्रता की ओर बढ़ता है। अंततः यह निश्चय हुआ कि इस विवाद का निर्णय धरती पर किसी मनुष्य से करवाया जाए। दोनों ने तय किया कि जो सबसे पहले उन्हें दिखाई देगा, वही इस प्रश्न का न्याय करेगा।

इस निर्णय के बाद दोनों देवियाँ पृथ्वी लोक पर उतरीं। वे खेतों, जंगलों, नदियों और गाँवों के ऊपर उड़ती हुई एक छोटे से गाँव में पहुँचीं। वहाँ एक साधारण किसान अपने खेत में हल चला रहा था। सूरज सिर पर था, और पसीने की बूँदें उसके चेहरे पर मोतियों की तरह चमक रही थीं। उसके कपड़े साधारण थे, पैर मिट्टी में सने हुए थे, लेकिन आँखों में शांति और चेहरे पर संतोष की चमक थी।

दोनों देवियाँ उसके पास पहुँचीं। किसान ने उन्हें देखा तो आदरपूर्वक हाथ जोड़ दिए। देवियाँ बोलीं, "हे मनुष्य, हम दोनों में यह विवाद चल रहा है कि हममें से कौन अधिक सुंदर है। तू हमारी इस समस्या का समाधान करेगा। पर ध्यान रख—जब तक तू इसका निर्णय नहीं करेगा, तब तक हम तुझे यहाँ से जाने नहीं देंगी।"

किसान चकित हुआ। उसे तुरंत समझ में आ गया कि यह अत्यंत कठिन स्थिति है। अगर वह लक्ष्मी देवी के पक्ष में बोलेगा तो दरिद्रता देवी उसे श्राप दे देंगी, और अगर दरिद्रता देवी के पक्ष में बोलेगा तो लक्ष्मी जी का कृपाभाव सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। यह एक ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर सीधा देना स्वयं के विनाश को बुलावा देना था। किसान ने अपनी छाती पर हाथ रखकर कुछ क्षण विचार किया, फिर एक मंद मुस्कान के साथ बोला—

"हे देवियों, आप दोनों की सुंदरता असंदिग्ध है। आपके सौंदर्य का वर्णन शब्दों में करना असंभव है। किंतु मुझे इतना कहना पड़ेगा कि आपकी सुंदरता समय और परिस्थिति के अनुसार भिन्न-भिन्न रूप में प्रकट होती है। दरिद्र देवी, जब आप किसी के घर से प्रस्थान करती हैं, तब संसार में आपसे अधिक सुंदर कोई नहीं लगता, क्योंकि आपके जाने से उस घर में फिर से आनंद, उत्साह और प्रकाश लौट आता है। और लक्ष्मी जी, जब आप किसी के घर में प्रवेश करती हैं, तब भी आपसे सुंदर कोई नहीं दिखाई देता, क्योंकि आपके आगमन से घर का हर कोना रत्नजड़ित हो उठता है, हर चेहरा मुस्कान से भर जाता है।"

किसान के मुख से यह बात सुनकर दोनों देवियाँ एक-दूसरे की ओर देखने लगीं। उनके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। वे जान गईं कि यह मनुष्य केवल श्रमशील ही नहीं, अपितु अत्यंत बुद्धिमान और तटस्थ भी है। लक्ष्मी जी बोलीं—"हे विवेकी पुरुष, तुम्हारी वाणी में अमृत है। तुमने किसी का अपमान किए बिना इतना सुंदर समाधान प्रस्तुत किया कि हम दोनों संतुष्ट हो गईं। तुम्हारी यह हाजिरजवाबी तुम्हें अनंत वैभव का अधिकारी बना देगी।"

दरिद्रता देवी ने भी प्रसन्न होकर कहा—"हे किसान, तुम्हारी विनम्रता और बुद्धि ने मेरे हृदय को भी शीतल कर दिया। मैं तुम्हारे घर कभी नहीं जाऊँगी। तुम्हारे द्वार के पास आते ही मैं लौट जाऊँगी।" दोनों देवियाँ किसान को आशीर्वाद देकर स्वर्ग लौट गईं।

किसान ने हाथ जोड़कर दोनों देवियों को प्रणाम किया। उसके हृदय में कृतज्ञता और शांति का सागर उमड़ पड़ा। उसने समझ लिया कि जीवन में केवल परिश्रम या पूजा ही नहीं, बल्कि परिस्थिति के अनुसार बोलने की कला भी उतनी ही आवश्यक है। हाजिरजवाबी केवल चतुराई नहीं होती, वह बुद्धि का शुद्धतम रूप है।

उस दिन से किसान के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवाह बना रहा। उसके गाँव के लोग भी उसकी प्रशंसा करने लगे। वे कहते—"उसके घर से दरिद्रता तो क्या, दुःख का नाम भी दूर हो गया है। वह जो बोले, उसमें देवत्व झलकता है।"

यह कथा केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि गहन शिक्षाप्रद भी है। यह बताती है कि जीवन में जब कोई कठिन स्थिति आये, तब संतुलित वाणी और विवेकपूर्ण उत्तर ही रक्षा कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखकर सही समय पर सही शब्द बोलता है, वह देवताओं तक को प्रसन्न कर सकता है। यही हाजिरजवाबी की दिव्य शक्ति है—जो संकट को अवसर में, और विवाद को वरदान में बदल देती है।

शैक्षिक गुणवत्ता में गिरावट पर आत्ममंथन करें

हम देश में शिक्षा के नए मॉडलों, डिजिटल प्रगति और कृत्रिम मेधा की उपलब्धियों पर गर्व करते हैं। तकनीक और इंटरनेट की ताकत में हम विकसित देशों की बराबरी का दावा करते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि आज भी शिक्षा से मिलने वाले जागरूकता के संस्कार आमजन तक नहीं पहुंच पाए हैं। कृत्रिम मेधा और रोबोटिक युग की चर्चा के बीच देश का बड़ा ग्रामीण हिस्सा अब भी इनसे वंचित है।

शिक्षा क्रांति का अर्थ यह है कि आधुनिक शिक्षा केवल अमीर और उच्च वर्ग तक सीमित न रहे, बल्कि गरीब वर्ग के बच्चों को भी समान अवसर और ज्ञान प्राप्त हो। सरकारी स्कूलों का स्तर इतना ऊंचा हो जाए कि गरीब छात्रों को महंगे, पश्चिमी शैली के स्कूलों की आवश्यकता न पड़े।

वास्तव में शिक्षा क्रांति के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, वे अभी तक साकार नहीं हो सके हैं। हाल ही में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की टिप्पणियां इस विफलता को उजागर करती हैं। उन्होंने कहा कि न केवल पंजाब, बल्कि देशभर के शिक्षा नियामक संस्थान अपने संस्थानों में न्यूनतम शैक्षणिक मानकों को लागू करने में असफल रहे हैं। नियामक संस्थाओं का दायित्व था कि वे शिक्षा को वैज्ञानिक, सुसंस्कृत और आधुनिक स्वरूप दें, लेकिन व्यवहार में वे केवल औपचारिकता निभा रही हैं। इस लापरवाही का परिणाम यह है कि स्कूलों और कॉलेजों की परीक्षाएं ही नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य निर्धारण वाली प्रतियोगी परीक्षाएं भी सुचारु रूप से नहीं हो पा रही हैं।

वर्तमान समय में न्यायपालिका की सबसे बड़ी चिंता शिक्षण क्षेत्र में फैलते फर्जीवाड़े को लेकर है। यह फर्जीवाड़ा लगातार बढ़ रहा है, परंतु पाठ्यक्रमों और पाठ्यपुस्तकों में आवश्यक सुधार के संकेत नहीं दिखते। बिना किसी ठोस योग्यता के बांटी जा रही डिग्रियां न केवल युवाओं के भविष्य को संकट में डालती हैं, बल्कि जनहित को भी नुकसान पहुंचाती हैं। हाल ही में पंजाब से खबरें सामने आईं कि कुछ कर्मचारी, जिनमें शिक्षक और डॉक्टर भी शामिल थे, फर्जी डिग्रियों के आधार पर वर्षों तक नौकरी करते रहे। जब प्रमोशन के समय जांच हुई, तब ये घोटाले उजागर हुए। आज देश का हर नौजवान विदेशों में कमाने का सपना देखता है। इंग्लैंड जैसी जगहों पर अंग्रेज़ी भाषा की योग्यता के लिए प्रमाणपत्र मांगे जाते थे, जिन्हें जाली तरीके से प्राप्त कर लिया जाता था। लेकिन इन फर्जी डिग्रियों के कारण विदेशों में न केवल उनके सपनों को झटका लगता, बल्कि दोयम दर्जे का जीवन भी जीना पड़ता था।

न्यायपालिका की एकल पीठ की सबसे बड़ी चिंता शिक्षा के बढ़ते व्यापारीकरण को लेकर है। बच्चों के स्कूल में दाखिले के साथ ही पहली कक्षा से ट्यूशन शुरू करवा दी जाती है और अभिभावक इसे अपनी जिम्मेदारी की समाप्ति मान लेते हैं। शिक्षा प्रणाली में व्यापारीकरण इस हद तक बढ़ गया है कि चाहे वह दाखिले की संयुक्त परीक्षाएं हों या आईएएस जैसी प्रतिष्ठित सेवाएं, हर स्तर पर कोचिंग संस्थानों का बोलबाला है। न्यायपीठ ने यह भी इंगित किया कि सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर्स से पैदा हुआ है, जिनका उद्देश्य शिक्षा नहीं, बल्कि व्यावसायिक लाभ है। इन संस्थानों से मिलने वाली तकनीकी डिग्रियों की वैधता पर सवाल उठते हैं। न्यायालय ने कहा है कि इंजीनियरिंग जैसी तकनीकी डिग्रियों को तभी मान्यता दी जाए जब वे एआईसीटीई से अनुमोदित हों।

वर्तमान परिवेश में निजी शिक्षा और कोचिंग संस्थानों का जाल इस कदर फैल गया है कि कई संस्थान किसी भी विश्वविद्यालय से डिग्री दिलवाने का दावा करते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हर वर्ष ऐसे अवैध और मान्यता-विहीन संस्थानों की सूची जारी करता है, जो नाम बदल-बदल कर फर्जी डिग्रियों का धंधा चला रहे हैं। पंजाब में ही 16 से अधिक निजी विश्वविद्यालय सक्रिय हैं, लेकिन उनका शैक्षणिक स्तर क्या है, यह गंभीर प्रश्न है। यदि हर डिग्री की विश्वसनीयता परखने के लिए एक और परीक्षा लेनी पड़ी, तो यह परीक्षा-दर-परीक्षा की प्रणाली भी एक अव्यवस्थित मूल्यांकन पद्धति बनकर रह जाएगी।

हर वर्ष परीक्षाओं के नियमों में बदलाव किए जाते हैं, फिर भी छात्रों की शिकायतें बनी रहती हैं। शिक्षा क्रांति का अर्थ केवल तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि ऐसा आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए जो व्यक्ति के भीतर ज्ञान और मूल्यों की ज्योति प्रज्वलित करे—न कि भौतिकवाद की ऐसी आंधी, जो सही और गलत की पहचान तक मिटा दे।

दुर्भाग्यवश, आज शिक्षा प्रणाली में बाजारीकरण इतना हावी हो गया है कि डिग्री को ज्ञान और अभ्यास से ऊपर रखा जा रहा है। इसमें शिक्षकों, नीति-निर्माताओं और पुस्तक संस्कृति के क्षरण की भी भूमिका है। यदि भारत को 2047 तक वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ना है तो शिक्षा की गिरावट पर गंभीर आत्ममंथन करना होगा।

अभियान

मातृत्व का पर्वः अहोई अष्टमी और संतान की मंगलकामना का अनंत व्रत

भारतीय संस्कृति में प्रत्येक पर्व, उपवास और अनुष्ठान के पीछे कोई न कोई गहरा भाव, पारिवारिक उद्देश्य और आध्यात्मिक संदेश छिपा होता है। यह केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि समाज में प्रेम, समर्पण और संवेदना को जीवित रखने का माध्यम भी है। इन्हीं महान पर्वों में से एक है अहोई अष्टमी—एक ऐसा व्रत जो मातृत्व की पवित्रता, त्याग और निःस्वार्थ प्रेम का जीवंत प्रतीक है। यह व्रत विशेष रूप से माताएं अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य, सुख-समृद्धि और दीर्घायु की कामना से करती हैं।

अहोई अष्टमी की कथा, पूजा-विधि और इसकी उत्पत्ति, सब कुछ मातृत्व के करुण भावों से जुड़ा हुआ है। इस व्रत का उल्लेख प्राचीन पुराणों और लोककथाओं में मिलता है, जो बताती हैं कि एक मां के हृदय की शक्ति संसार की हर शक्ति से अधिक होती है। यह व्रत हर वर्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है, ठीक करवा चौथ के चार दिन बाद। इस वर्ष यह शुभ तिथि सोमवार, 13 अक्तूबर को मनाई जा रही है। अष्टमी तिथि का प्रारंभ दोपहर 12 बजकर 24 मिनट से होगा और अगले दिन 14 अक्तूबर को सुबह 11 बजकर 9 मिनट पर समाप्त होगा। पूजा का उत्तम मुहूर्त शाम 5 बजकर 59 मिनट से 7 बजकर 14 मिनट तक रहेगा।

इस दिन माताएं प्रातः स्नान के बाद संकल्प लेती हैं कि वे पूरे दिन निर्जला व्रत रखेंगी। न तो अन्न ग्रहण करती हैं और न जल पीती हैं। पूरा दिन वे अपने बच्चों के मंगल की भावना में लीन रहती हैं। यह व्रत इतना कठोर होता है कि इसे करने के लिए अटूट श्रद्धा और आत्मसंयम की आवश्यकता होती है। संध्या समय तारों या चंद्रमा के दर्शन के बाद पूजा संपन्न होती है और तभी माताएं व्रत खोलती हैं। कुछ परंपराओं में चंद्र दर्शन के बाद, तो कुछ में केवल तारों के दर्शन के बाद उपवास तोड़ा जाता है।

अहोई अष्टमी के पीछे एक अत्यंत मार्मिक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय एक साहूकार और उसकी पत्नी सात पुत्रों के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। दीपावली से कुछ दिन पहले जब उनकी पत्नी घर की सफाई और सजावट में लगी हुई थी, तो उसे मिट्टी की आवश्यकता हुई। वह मिट्टी लाने जंगल की ओर गई और मिट्टी खोदते समय अनजाने में एक स्याह (सेह या नेवले) के बच्चों को क्षति पहुँचा दी। उस स्याह ने क्रोधित होकर उसे श्राप दे दिया—"जैसे तूने मेरे बच्चों को मारा है, वैसे ही तेरे भी सारे बच्चे मर जाएँ।" उस दिन से उसके घर में दुख का सिलसिला शुरू हो गया और उसके सातों पुत्र एक-एक करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। दुःख से व्याकुल होकर वह साहूकार की पत्नी तीर्थों में भटकने लगी, परंतु उसे कहीं शांति नहीं मिली। अंततः एक दिन किसी साध्वी ने उसे अहोई माता की उपासना का मार्ग बताया और कहा कि यदि वह सच्चे मन से यह व्रत करेगी, तो अहोई माता उसे फिर से संतान-सुख प्रदान करेंगी। उसने पूरे श्रद्धाभाव से अहोई अष्टमी का व्रत किया। अहोई माता उसकी भक्ति से प्रसन्न हुईं और उसके मृत बच्चे पुनः जीवित हो उठे। तभी से यह व्रत संतान की दीर्घायु और रक्षा के लिए किया जाने लगा।

अहोई अष्टमी की पूजा का तरीका भी अत्यंत सुंदर और प्रतीकात्मक है। संध्या के समय घर की किसी दीवार या पूजा वाले स्थान पर अहोई माता की चित्राकृति बनाई जाती है। इसमें अहोई माता के साथ आठ छोटे बिंदु बनाए जाते हैं, जो आठ पुत्रों या आठ प्रकार के आयुष्मान भावों के प्रतीक माने जाते हैं। इसके साथ स्याह या नेवले का भी चित्र बनाया जाता है, जो उस घटना की स्मृति के रूप में पूजा जाता है। कुछ लोग आजकल अहोई माता की मुद्रित तस्वीर या कैलेंडर पर बनी छवि की पूजा करते हैं, किंतु परंपरा के अनुसार स्वयं बनाना अधिक शुभ माना जाता है।

पूजा के लिए मिट्टी या पीतल का करवा लिया जाता है, जिसमें स्वच्छ जल भरा जाता है। करवे के मुख को मिट्टी, दूर्वा या घास से बंद किया जाता है। करवा मातृत्व की कोख का प्रतीक है—जो जीवन को धारण करती है, पोषण करती है और सुरक्षित रखती है। पूजा में हलवा, पूरी, पुआ, चावल और अष्ट संख्या के पकवान बनाए जाते हैं, जो अहोई माता को अर्पित किए जाते हैं। कथा सुनने के बाद अर्घ्य दिया जाता है और व्रत का समापन तारा या चंद्र दर्शन के साथ किया जाता है।

उत्तर भारत के अधिकांश प्रांतों—उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली—में यह व्रत बड़ी श्रद्धा से किया जाता है। समय के साथ अब यह पर्व विदेशों में बसे भारतीय समुदायों में भी लोकप्रिय हो गया है। सोशल मीडिया और टेलीविजन के माध्यम से यह अब अखिल भारतीय पर्व का स्वरूप ले चुका है। चाहे कोई गाँव हो या महानगर, हर जगह यह व्रत मां और संतान के अटूट बंधन का उत्सव बन गया है।

अहोई अष्टमी केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि मां के त्याग, प्रेम और असीम धैर्य का प्रतीक है। जब कोई मां पूरे दिन जल तक का त्याग करके केवल अपने बच्चों के मंगल के लिए ध्यान करती है, तब वह प्रकृति की सबसे दिव्य ऊर्जा का संचार करती है। यही मातृत्व की शक्ति है—जो अपने प्रेम से संतानों को सुरक्षित रखती है, और अपने आशीर्वाद से जीवन को अमर बना देती है।

यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा सौभाग्य धन या पद में नहीं, बल्कि अपने परिवार के सुख, बच्चों के स्वास्थ्य और उनकी दीर्घायु में है। जिस घर में मां अपने बच्चों के लिए यह व्रत करती है, वहाँ सदैव मंगल, शांति और समृद्धि का निवास रहता है। अहोई अष्टमी का हर क्षण मातृत्व का उत्सव है—जहाँ एक मां स्वयं को त्यागकर अपने बच्चों के भविष्य को संवारने का संकल्प लेती है। यह व्रत बताता है कि मां केवल शरीर नहीं, बल्कि ईश्वर की वह अभिव्यक्ति है जिसके बिना सृष्टि का अस्तित्व अधूरा है। अहोई माता का यह पर्व इस सत्य का स्मरण कराता है कि संसार की सबसे महान शक्ति मातृत्व है—जो आशीर्वाद भी है, आराधना भी और संपूर्ण सृष्टि का सार भी।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA

विकास सप्ताह : 14 अक्टूबर, कृषि विकास दिवस

विकास सप्ताह के तहत गुजरात में 14-15 अक्टूबर को आयोजित होगा 'रबी कृषि महोत्सव-2025'

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और कृषि मंत्री श्री राघवजी पटेल पंचमहाल-गोधरा के छबनपुर गांव में करेंगे राज्यव्यापी शुभारंभ

कृषि मंत्री श्री राघवजी पटेल :-

- राज्य में 261 स्थानों पर आयोजित होने वाले जिला और तहसील स्तरीय कार्यक्रमों का मंत्री, सांसद और विधायक सहित पदाधिकारी करेंगे शुभारंभ
- महोत्सव में कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के 5 लाख से अधिक लाभार्थियों को 500 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता वितरित की जाएगी
- दो दिवसीय रबी कृषि महोत्सव में गुजरात के 3 लाख से अधिक किसान लेंगे हिस्सा
- महोत्सव के दौरान विभिन्न स्थानों पर आयोजित होंगे निःशुल्क पशु स्वास्थ्य

(जीएनएस)। गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणादायी जनसेवा यात्रा के 24 वर्ष पूरे होने के अवसर पर समग्र गुजरात में 7 से 15 अक्टूबर के दौरान विभिन्न थीमों पर आधारित 'विकास सप्ताह' मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 14 अक्टूबर को 'कृषि विकास दिवस' के रूप में मनाया जाएगा।

कृषि विकास दिवस के दौरान कृषि और किसान कल्याण विभाग की ओर से 14 और 15 अक्टूबर को 'रबी कृषि महोत्सव-2025' का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य किसानों को मौजूदा समय के अनुरूप कृषि पद्धतियों, टेक्नोलॉजी और नवीन दृष्टिकोण से परिचित कराना है। कृषि क्षेत्र और राज्य के किसानों को समर्पित 'कृषि विकास दिवस' के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और कृषि मंत्री श्री राघवजी पटेल पंचमहाल-गोधरा के छबनपुर गांव में राज्यव्यापी 'रबी कृषि महोत्सव-2025' का शुभारंभ करेंगे।

कृषि मंत्री श्री राघवजी पटेल ने रबी कृषि महोत्सव-2025 के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि विकास सप्ताह के तहत 14 और 15 अक्टूबर को राज्य में कुल 261 स्थानों पर जिला और तहसील स्तरीय रबी कृषि महोत्सव-2025 का आयोजन किया जाएगा। गुजरात सरकार के मंत्री, सांसद और विधायकों सहित विभिन्न पदाधिकारी और उच्च अधिकारी जिला और तहसील स्तरीय कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगे। इस दो दिवसीय रबी कृषि महोत्सव में गुजरात के लगभग 3 लाख से अधिक किसान हिस्सा लेंगे।

कृषि मंत्री ने कहा कि रबी कृषि महोत्सव के दौरान गुजरात सरकार राज्य के प्रगतिशील किसानों और पशुपालकों को विशेष रूप से सम्मानित करेगी। इसके अलावा, कृषि, बागवानी और पशुपालन विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 5 लाख से अधिक लाभार्थी किसानों को 500 करोड़ रुपए की सहायता के मंजूरी पत्र और सहायता आदेश का भी वितरण किया जाएगा। इतना ही नहीं, राज्य के कृषि वैज्ञानिक और कृषि विशेषज्ञ किसानों को उनके क्षेत्रों में रबी सीजन में उगाई जाने वाली फसलों के संबंध में तकनीकी मार्गदर्शन के अलावा प्राकृतिक खेती और बागवानी फसलों में नवीनतम टेक्नोलॉजी जैसे विभिन्न विषयों पर भी मार्गदर्शन देंगे। साथ ही, प्रगतिशील किसानों और किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के प्रतिनिधियों द्वारा भी विभिन्न विषयों पर वक्तव्य दिए जाएंगे।

इस महोत्सव में किसानों को रबी फसलों की बुवाई के लिए आधुनिक कृषि तकनीकों और प्राकृतिक खेती की पद्धति के संबंध में जागरूक करने के लिए फसल परिचर्चा, नई टेक्नोलॉजी पर आधारित कृषि प्रदर्शनी और किसान-उन्मुख विभिन्न सहायता योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी।

इसके अलावा, राज्य की सभी तहसीलों में किसान प्राकृतिक कृषि के मॉडल फॉर्म का दौरा करेंगे। विशेषज्ञों एवं प्रगतिशील किसानों द्वारा खेती से जुड़ी किसानों की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन दो दिनों के दौरान पशुपालन विभाग ने भी विभिन्न स्थानों पर निःशुल्क पशु स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया है, जिनका पशुपालक लाभ उठा सकते हैं।

कृषि मंत्री ने कहा कि रबी कृषि महोत्सव कार्यक्रम स्थलों पर प्रगतिशील किसानों के उत्पादों, प्राकृतिक खेती के आयामों, ड्रोन जैसी आधुनिक कृषि तकनीक, कृषि और मृदा परीक्षण तथा किसान उपयोगी अनुसंधानों सहित नए जमाने के उर्वरकों के इस्तेमाल को लेकर किसानों में जागरूकता पैदा करने वाली विभिन्न प्रदर्शनियों सहित कुल 2800 प्रदर्शनी स्टॉल लगाए जाएंगे। इनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लैंड सीडिंग (भू-आलेखों का सत्यापन), किसान पंजीकरण के अंतर्गत ई-केवाईसी और स्व-पंजीकरण से संबंधित स्टॉल तथा कृषि यंत्रीकरण और कृषि प्रसंस्करण के यंत्रों एवं औजारों के स्टॉल भी शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 2005 में कृषि महोत्सव की एक नई परंपरा शुरू की थी, ताकि कृषि वैज्ञानिक और विशेषज्ञ किसानों के साथ सीधे बातचीत कर उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें और उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान करने के साथ ही नई खेत पद्धतियों से अवगत करा सकें। कृषि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए शुरू की गई इस परंपरा को आज मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में कृषि मंत्री श्री राघवजी पटेल बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं।

विकास सप्ताह : 14 अक्टूबर, कृषि विकास दिवस

प्राकृतिक खेती ने डांग की मंगीबेन को बनाया लखपति दीदी, श्रीअन्न से मूल्यवर्धित उत्पाद बनाकर अन्य महिलाओं को दी प्रेरणा

- प्राकृतिक कृषि से आई समृद्धि : मंगीबेन ने पहले ही महीने नागली (श्रीअन्न) से बने 15,000 रुपए के उत्पाद बेचे, आज उनकी यूनिट प्रतिमाह 60,000 रुपए के उत्पाद बेचती है
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात में प्राकृतिक खेती को मिला बढ़ावा

(जीएनएस)। गांधीनगर : 7 अक्टूबर, 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सेवा और समर्पण के 24 वर्ष पूरे होने के अवसर पर गुजरात 7 से 15 अक्टूबर तक विकास सप्ताह मना रहा है। इसके अंतर्गत राज्य में कृषि क्षेत्र में हुई प्रगति को ध्यान में रखते हुए 14 अक्टूबर का दिन 'कृषि विकास दिवस' के रूप में मनाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात में किसानों को प्राकृतिक कृषि अपनाने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया है, इसके परिणामस्वरूप राज्य के किसान कृषि की टिकाऊ पद्धति अपनाकर मुनाफा कमा रहे हैं। आज, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है।

'आपणुं डांग, प्राकृतिक डांग' अभियान से आदिवासी किसानों के जीवन में आया बदलाव

जब भी प्राकृतिक कृषि की बात होती है, एक अभियान का नाम अनायास ही जुबान पर आता है, वो है 'आपणुं डांग, प्राकृतिक डांग' यानी 'हमारा डांग, प्राकृतिक डांग।' इस अभियान के माध्यम से वर्ष 2021 में प्राकृतिक सौंदर्य से लकदक डांग जिले को संपूर्ण रूप से रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती वाला जिला घोषित किया गया था। तब से, यह पहल आदिवासी किसानों के जीवन में एक शानदार बदलाव लेकर आई है। इस बदलाव का चेहरा बनकर उभरी हैं आहवा जिले के धवलीदोड़ गांव की मंगीबेन, जो आज प्राकृतिक खेती अपनाकर लखपति दीदी बन गई हैं।

डांग की मंगीबेन का साहसिक प्रयास लाया रंग : स्थानीय श्रीअन्न-नागली से बनाए मूल्यवर्धित उत्पाद

मंगीबेन का साहस से समृद्धि तक सफर दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणादायी बन गया है। मिशन मंगलम (एनआरएलएम) के तहत फील्ड को-ऑर्डिनेटर ने मंगीबेन को स्वयं सहायता समूह (एसएचओ) में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया था। डांग जैसे वन क्षेत्र और वहां की समृद्ध वन उपज के महत्व को समझते हुए मंगीबेन ने साहस जुटाकर एक नया उद्यम शुरू किया। डांग में उगाए जाने वाले श्रीअन्न नागली (रागी की एक किस्म) को बहुत ही पौष्टिक माना जाता है। इसके स्वास्थ्य लाभ और बाजार संभावनाओं को ध्यान में रखकर मंगीबेन ने नागली की खेती और प्रसंस्करण की दिशा में कदम बढ़ाया। उन्होंने अपने समूह के साथ मिलकर नागली से मूल्यवर्धित उत्पाद बनाने की शुरुआत की।

एक खेतिहर मजदूर से उद्यमी बनीं मंगीबेन

स्वयं सहायता समूह में शामिल होने से पहले मंगीबेन एक सीजनल यानी मौसमी खेतिहर मजदूर के रूप में मनरेगा के तहत काम करती थीं। मंगीबेन के जीवन में एक नया और सुखद मोड़ तब आया, जब उन्होंने ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था (आरएसईटीआई) से श्रीअन्न के प्रसंस्करण का निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के बाद उन्होंने नागली आटा, लड्डू, कुकीज और स्वास्थ्यप्रद मिश्रण बनाना सीखा और छोटे पैमाने पर अपना एक उद्योग शुरू किया। जब गुजरात सरकार ने डांग को पूरी तरह से रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती वाला जिला घोषित किया, तब मंगीबेन ने नागली की ऑर्गेनिक (जैविक) खेती करने का रास्ता चुना। टिकाऊ खेती से उत्पादों की न्यूट्रीशन वैल्यू यानी पोषण मूल्य तो बढ़ा ही, साथ ही उनका बाजार मूल्य भी बढ़ गया।

पहले ही महीने बेचे 15,000 रुपए के उत्पाद, आज उनकी यूनिट की बिक्री प्रतिमाह 60,000 रुपए है

मंगीबेन ने उद्योग शुरू करने के पहले ही महीने में 15,000 रुपए के उत्पाद बेचे। इसके बाद, उन्होंने अपने स्वयं सहायता समूह से 10 और महिलाओं को अपनी इस गतिविधि में शामिल किया। आज, उनकी यूनिट प्रतिमाह 60,000 रुपए तक के नागली के उत्पादों का उत्पादन और बिक्री करती है और 20,000 रुपए की मासिक आय अर्जित करती है। सरकार के सहयोग से वे विभिन्न प्रदर्शनियों और मेलों में हिस्सा लेती हैं, बाजार का विस्तार करती हैं और प्राकृतिक खेती के राष्ट्रीय मिशन के तहत ब्रांडिंग और प्रमोशन की पहलों का लाभ प्राप्त करती हैं। मंगीबेन का खेतिहर मजदूर से उद्यमी बनने तक का सफर, लखपति दीदी की पहल को भी उजागर करता है। उनका यह सफर दर्शाता है कि कैसे प्राकृतिक खेती का रास्ता डांग की महिलाओं के लिए नियमित रोजगार का माध्यम बन गया है और दूसरी महिलाओं को भी इस दिशा में काम करने की प्रेरणा दी है। इतना ही नहीं, यह स्थानीय संसाधनों के उपयोग और सामुदायिक भागीदारी के जरिए विकास का टिकाऊ मॉडल भी दर्शाता है।

रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव द्वारा मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के अंतर्गत बिलिमोरा बुलेट ट्रेन स्टेशन का दौरा किया गया

(जीएनएस)। केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आज मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के निर्माणाधीन बिलिमोरा बुलेट ट्रेन स्टेशन का दौरा किया। उनके साथ वलसाड के सांसद श्री धवल पटेल और गणदेवी के विधायक श्री नरेश पटेल भी थे।

इस दौरान, मंत्री ने बिलिमोरा बुलेट ट्रेन स्टेशन पर चल रहे निर्माण और ट्रैक बिछाने के कार्यों की समीक्षा की।

A. बिलिमोरा बुलेट ट्रेन स्टेशन

बिलिमोरा शहर आम के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। स्टेशन के फसाड का डिज़ाइन आम के बागानों से प्रेरित है, जो शहर की प्राकृतिक सुंदरता और स्थानीय पहचान को प्रतिबिंबित करता है। आंतरिक और प्लेटफ़ॉर्म क्षेत्र को पर्याप्त प्राकृतिक रोशनी और वेंटिलेशन के साथ डिज़ाइन किया गया है। फॉल्स सीलिंग को एंटी-वाइब्रेशन हैंगर से लगाया गया है ताकि ट्रेनों की तेज गति से होने वाले कंपन का असर फिटिंग्स पर न पड़े। स्टेशन आधुनिक यात्री सुविधाओं से सुसज्जित है, जैसे कि वेटिंग लाउंज, नर्सरी, शौचालय, रिटेल आउटलेट आदि। विभिन्न स्तरों पर सहज आवागमन के लिए कई लिफ्ट और एस्केलेटर लगाए जा रहे हैं, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों, विकलांगों और बच्चों वाले परिवारों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया गया है।

स्टेशन परिसर में हरियाली और ताजगीपूर्ण वातावरण बनाने के लिए पौधारोपण किया जा रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए पिक-अप और ड्रॉप-ऑफ ज़ोन, बसों, कारों और दोपहिया वाहनों के लिए अलग पार्किंग, ईवी पार्किंग आदि की योजना बनाई गई है।

सुविधा और स्थिरता को मिलाते हुए, स्टेशन में IGBC (इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल) की कई विशेषताएँ शामिल की गई हैं, जैसे कि पानी का कुशल उपयोग, वर्षा जल संचयन, लो-फ्लो सैनिटरी फिटिंग्स, आंतरिक हिस्सों में कम गर्मी प्रवेश, कम वाष्पशील कार्बनिक यौगिक वाले पेंट आदि।

बिलिमोरा के पास केसली गाँव में, नवसारी जिले की अंबिका नदी के किनारे स्थित, यह स्टेशन विभिन्न परिवहन माध्यमों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है:

- बिलिमोरा रेलवे स्टेशन: 6 कि.मी.
- बिलिमोरा बस डिपो: 6 कि.मी.
- राष्ट्रीय राजमार्ग NH-360: 2.5 कि.मी.

स्टेशन की मुख्य विशेषताएँ:

- कुल निर्मित क्षेत्रफल: 38,394 वर्ग मीटर
- स्टेशन भवन में दो स्तर शामिल हैं: ग्राउंड कम कांसॉर्स स्तर: पार्किंग, पिक-अप/ड्रॉप-ऑफ, पैदल यात्री प्लाज़ा, सुरक्षा जांच चौकियां, वेटिंग लाउंज, शौचालय, लिफ्ट, एस्केलेटर, सीढ़ियाँ, कियोस्क, टिकटिंग काउंटर आदि।
- प्लेटफ़ॉर्म स्तर: दो प्लेटफ़ॉर्म और चार ट्रैक
- हाई-स्पीड ट्रेनों के लिए 425 मीटर लंबा प्लेटफ़ॉर्म

स्टेशन की प्रगति

रेल और प्लेटफ़ॉर्म स्लैब कास्टिंग का कार्य तथा बिल्डिंग में स्ट्रक्चरल स्टील का कार्य पूरा हो चुका है। आर्किटेक्चरल फिनिशिंग और MEP (मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग) कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं।

B. बिलिमोरा बुलेट ट्रेन स्टेशन का ट्रैक निर्माण कार्य

बिलिमोरा बुलेट ट्रेन स्टेशन पर आरसी ट्रैक बेड निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुके हैं और रेल लेइंग कार (RLC) का उपयोग करके अस्थायी ट्रैक की स्थापना सक्रिय रूप से प्रगति पर है।

रेल लेइंग कार ट्रैक कंस्ट्रक्शन बेस (TCB) से 200-मीटर वेल्डेड रेल पैनलों को स्थापना स्थल तक ले जाने की सुविधा प्रदान करती है, जिससे रेल पैनलों को यांत्रिक रूप से संभालने और रखने में आसानी होती है और मानवीय हस्तक्षेप न्यूनतम होता है।

320 कि.मी./घंटा की गति पर ट्रेनों के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सर्वेक्षण की सटीकता को सर्वोच्च महत्व दिया जाता है। उच्चतम विश्वसनीयता और सटीकता वाले अत्याधुनिक सर्वेक्षण उपकरण तैनात किए जाते हैं, और सभी सर्वेक्षण चरणों का बहु-स्तरीय सत्यापन किया जाता है। मामूली निर्माण भिन्नताओं की प्रभावी भरपाई के लिए रेफरेंस पिन (reference pin) सर्वे और रिग्रेशन एनालिसिस विधियों को अपनाया जाता है।

बिलिमोरा स्टेशन में दो लूप लाइनें हैं, जिनमें चार 18 में से 1 टर्नआउट्स मूवेबल क्रॉसिंग्स के साथ और दो 18 में से 1 क्रॉसओवर्स शामिल हैं। मुख्य लाइन 12 में से 1 टर्नआउट के माध्यम से शाखाबद्ध होती है ताकि कन्फर्मेशन कार बेस को समायोजित किया जा सके।

C. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की प्रगति (10 अक्टूबर 2025 तक)

भारत का पहला 508 कि.मी. लंबा बुलेट ट्रेन कॉरिडोर मुंबई और अहमदाबाद के बीच निर्माणाधीन है।

- 508 कि.मी. में से, 325 कि.मी. वायाडक्ट और 400 कि.मी. पियर का काम पूरा हो चुका है
- 17 नदी पुल, 05 PSC (प्रि-स्ट्रेस्ड कंक्रीट) ब्रिज और 10 स्टील ब्रिज पूरे हो चुके हैं
- 216 कि.मी. क्षेत्र में 4 लाख से अधिक नॉइज़ बैरियर लगाए गए हैं
- 217 ट्रैक कि.मी. RC ट्रैक बेड का निर्माण पूरा हो चुका है
- लगभग 57 रूट कि.मी. में 2300 से अधिक OHE मास्ट लगाए जा चुके हैं
- पालघर जिले में 07 पहाड़ी सुरंगों पर खुदाई का काम प्रगति पर है
- BKC और शिलफाटा (महाराष्ट्र) के बीच 21 कि.मी. टनल में से 5 कि.मी. NATM टनल की खुदाई हो चुकी है
- सूरत और अहमदाबाद में रोलिंग स्टॉक डिपो का निर्माण प्रगति पर है
- गुजरात के सभी स्टेशनों पर सुपरस्ट्रक्चर का कार्य उन्नत चरण में है। महाराष्ट्र में तीनो एलिवेटेड स्टेशन का कार्य शुरू हो गया है तथा मुंबई अंडरग्राउंड स्टेशन पर बेस स्लैब कास्टिंग प्रगति पर है

पश्चिम रेलवे चलायेगी साबरमती-गोरखपुर और साबरमती-बेगूसराय के बीच अनारक्षित फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा आगमी दिवाली और छठ पूजा त्योहारों के मद्देनजर यात्रियों की मांग एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए साबरमती-गोरखपुर और साबरमती-बेगूसराय के बीच अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें विशेष किराये पर चलाने का निर्णय लिया गया है। इन स्पेशल ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है:

ट्रेन संख्या 09429/09430 साबरमती-गोरखपुर त्रि-साप्ताहिक अनारक्षित स्पेशल ट्रेन विशेष किराए पर (12 फेरे)

ट्रेन संख्या 09429 साबरमती-गोरखपुर त्रि-साप्ताहिक अनारक्षित स्पेशल साबरमती से 16 अक्टूबर 2025 से 26 अक्टूबर 2025 तक प्रति गुरुवार, शुक्रवार और रविवार को सुबह 08:50 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन सुबह 10:00 बजे गोरखपुर पहुचेंगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 09430 गोरखपुर-साबरमती त्रि-साप्ताहिक अनारक्षित स्पेशल गोरखपुर से 17 अक्टूबर 2025 से 27 अक्टूबर 2025 तक प्रति शुक्रवार, शनिवार और सोमवार को दोपहर 13:00 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन दोपहर 15:30 बजे साबरमती पहुचेंगी।

मार्ग में दोनों दिशाओं में यह ट्रेन महेसाणा, पालनपुर, आबूरोड, मारवाड़ जं., अजमेर, जयपुर, गांधी नगर जयपुर, दौसा, बाँदीकुई जं., भरतपुर, ईदगाह आगरा, टुंडला, इटावा, गोविंदपुरी,उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, मनकापुर एवं बस्ती स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में सभी अनारक्षित श्रेणी के कोच रहेंगे।

ट्रेन संख्या 09431/09432 साबरमती-बेगूसराय अनारक्षित स्पेशल ट्रेन विशेष किराए पर (28 फेरे)

ट्रेन संख्या 09431 साबरमती-बेगूसराय अनारक्षित स्पेशल साबरमती से 14 अक्टूबर 2025 से 27 अक्टूबर 2025 तक प्रतिदिन दोपहर 12:05 बजे प्रस्थान करेगी तथा तीसरे दिन सुबह 08:00 बजे बेगूसराय पहुचेंगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 09432 बेगूसराय-साबरमती अनारक्षित स्पेशल बेगूसराय से 16 अक्टूबर 2025 से 29 अक्टूबर 2025 तक प्रतिदिन दोपहर 12:00 बजे प्रस्थान करेगी तथा तीसरे दिन सुबह 05:00 बजे साबरमती पहुचेंगी।

मार्ग में दोनों दिशाओं में यह ट्रेन महेसाणा, पालनपुर, आबूरोड, फालना, मारवाड़ जं.,ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, दौसा, बाँदीकुई जं., भरतपुर, ईदगाह आगरा, टुंडला, इटावा, गोविंदपुरी, सुबेदारगंज, मिर्ज़ापुर, पं. दीन दयाल उपाध्याय जं., बक्सर, आरा, दानापुर, पाटलिपुत्र जं., सोनपुर, हाजीपुर एवं बरौनी जं. स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में सभी अनारक्षित श्रेणी के कोच रहेंगे।

ट्रेनों के परिचालन समय, ठहराव और संरचना से सम्बंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

श्री अश्विनी वैष्णव ने वलसाड में आरपीएफ स्थापना दिवस परेड में भाग लिया और अनुकरणीय सेवा के लिए पुरस्कार विजेताआरपीएफ कर्मियों को किया सम्मानित

माननीय मंत्री ने भारतीय रेल में हो रहे व्यापक परिवर्तन पर प्रकाश डाला; आरपीएफ के लिए उन्नत तकनीकी उन्नयन और प्रशिक्षण पहल की घोषणा की

(जीएनएस)। माननीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव 13 अक्टूबर, 2025 को आरपीएफ क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, वलसाड में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की स्थापना दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान, केंद्रीय मंत्री ने यात्रियों की जान बचाने में उनके साहसी प्रयासों के लिए 41 आरपीएफ कर्मियों को सम्मानित किया, जिन्हें सराहनीय सेवा के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पदक, जीवन रक्षा पदक आदि से सम्मानित किया गया था। ये पुरस्कार देश के रेलवे नेटवर्क की सुरक्षा में आरपीएफ की अनुकरणीय सेवा को दर्शाते हैं तथा बल के अन्य सदस्यों को नए जोश के साथ अपने समर्पित प्रयासों को जारी रखने के लिए प्रेरित करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने आरपीएफ परेड की औपचारिक सलामी भी ली, जो अनुशासन और प्रतिबद्धता का एक उल्लेखनीय प्रदर्शन था। मंत्री ने परेड के दौरान कर्मियों द्वारा प्रदर्शित अनुशासन, सटीकता और समर्पण के उच्च स्तर की सराहना की।

अपने संबोधन में श्री वैष्णव ने आरपीएफ कर्मियों को उनके स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई दी और यात्रियों एवं रेल संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने में उनके अटूट समर्पण और प्रतिबद्धता की सराहना की। मंत्री महोदय ने हाल ही में हुए महाकुंभ के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुरक्षित एवं सुगम यात्रा सुनिश्चित करने में आरपीएफ की उल्लेखनीय सेवा की भी सराहना की।

केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेल एक ऐतिहासिक परिवर्तन के दौर से गुज़र रहा है। पिछले 11 वर्षों में, लगभग 35,000 किलोमीटर नई रेल पटरियाँ बिछाई गई हैं और 99% रेलवे नेटवर्क (लगभग 60,000 किलोमीटर) का विद्युतीकरण किया जा चुका है। वर्तमान में लगभग 150 वंदे भारत और 30 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं, जो यात्रियों को विश्वस्तरीय यात्रा का अनुभव प्रदान करती हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1300 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, जिनमें से 110 स्टेशनों का उद्घाटन हो चुका है और शेष पर काम तेज़ी से प्रगति पर है।

उन्होंने आगे कहा कि त्योहारी सीज़न की मांग को पूरा करने के लिए दिवाली और छठ के लिए रिकॉर्ड संख्या में 12,000 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिससे सभी यात्रियों के लिए सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित हो रही है।

श्री वैष्णव ने अपने संबोधन में कहा कि कवच प्रणाली को दिल्ली-हावड़ा और दिल्ली-मुंबई जैसे प्रमुख मार्गों पर तेज़ी से लागू किया जा रहा है और यह उन्नत चरण पर है। कवच को 1200 इंजनों पर लगाया जा चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि हर साल लगभग 7000 कोच बनाए जा रहे हैं, जबकि लोगों की सुविधा के लिए 3500 सामान्य कोच भी जोड़े गए हैं।

उन्होंने आगे कहा कि रेलवे सुरक्षा बल में आधुनिक प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है और इस दिशा में आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

इस कार्यक्रम में वलसाड के संसद सदस्य श्री धवल पटेल; वलसाड के विधायक श्री भरतभाई पटेल; कपराडा के विधायक श्री जीतूभाई चौधरी; उमरगाम के विधायक श्री रमणलाल पाटकर; आरपीएफ की महानिदेशक श्रीमती सोनाली मिश्रा; पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता; पश्चिम रेलवे के पुलिस महानिरीक्षक / प्रमुख मुख्य सुरक्षा आयुक्त श्री अजय सदानी; मुंबई सेंट्रल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री पंकज सिंह और पश्चिम रेलवे के मुख्यालय और मंडल के अन्य वरिष्ठ रेल अधिकारी उपस्थित थे।

आरपीएफ स्थापना दिवस परेड आरपीएफ सदस्यों और उनके परिवारों द्वारा मनाई जाती है। यह जनता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की पुष्टि का दिन है। आरपीएफ एक करुणामयी शक्ति के रूप में उभरी है क्योंकि यह रेलवे के संपर्क में आने वाली महिलाओं, बच्चों, बीमारों, बुजुर्गों, दिव्यांगों और देखभाल व सुरक्षा की आवश्यकता वाले अन्य लोगों की सहायता करती रही है। यह बल रेल यात्रियों को सुरक्षित, संरक्षित और आरामदायक यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए चौबीसों घंटे कार्यरत है। परिवहन सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर, आतंकवादी गतिविधियों के विरुद्ध निवारक कार्रवाई करके, मानव तस्करी सहित अपराधों से लड़कर, अपराधों का पता लगाने में पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता करके, तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहायता करके, यह राष्ट्रीय सुरक्षा ग्रिड में एक महत्वपूर्ण हितधारक बन गया है।

रेलवे सुरक्षा बल ने "सेवा ही संकल्प" के उद्देश्य को साकार करने के लिए राष्ट्र और नागरिकों की सेवा के लिए पूरी लगन, ईमानदारी और कड़ी मेहनत के साथ खुद को समर्पित किया है और अपने आदर्श वाक्य "यशो लभस्व" अर्थात "महिमा प्राप्त करें" की दिशा में काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

आंबलियासन – विजापुर रेल खंड पर स्पीड ट्रायल दिनांक 14 अक्टूबर, 2025 को

सभी से रेल पटरी से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मण्डल पर आंबलियासन से विजापुर के बीच गेज परिवर्तन का कार्य अपने अंतिम चरण में है। इस कार्य के अंतर्गत नव-निर्मित रेल पटरी पर दिनांक 14 अक्टूबर, 2025 को सायं 18.00 बजे से किमी 87/1 से किमी 46/2 के बीच अधिकतम 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्पीड ट्रायल किया जाएगा।

स्पीड ट्रायल रेलवे की एक अनिवार्य तकनीकी प्रक्रिया है, जो रेल परिचालन शुरू करने से पूर्व ट्रैक की गुणवत्ता, सुरक्षा एवं स्थिरता की जांच के लिए की जाती है। इस दौरान ट्रैक पर विभागीय ट्रेनें, माप यंत्र और तकनीकी टीमें कार्यरत रहेंगी। इसलिए आम जनता, मजदूरों, किसानों एवं स्थानीय निवासियों से विशेष अनुरोध है कि वे रेलवे ट्रैक के समीप न जाएँ, ट्रैक को किसी भी स्थिति में पार न करें, तथा बच्चों और पशुओं को रेल लाइन से दूर रखें। सुरक्षा एवं जनहित के दृष्टिकोण से सभी से सहयोग की अपेक्षा है ताकि यह कार्य सुरक्षित, सफल एवं समय पर पूर्ण हो सके। यह गेज परिवर्तन परियोजना क्षेत्र की जनता को बेहतर रेल कनेक्टिविटी और विकास का नया आयाम प्रदान करेगी।

दक्षिण अफ्रीका में बस दुर्घटना: पर्वतीय इलाके में 42 लोगों की मौत

(जीएनएस)। जोहानिसबर्ग। दक्षिण अफ्रीका के उत्तर में स्थित पर्वतीय क्षेत्र में रविवार को हुई एक भयंकर बस दुर्घटना में कम से कम 42 लोगों की जान चली गई। दुर्घटना राजधानी प्रिटोरिया से लगभग 400 किलोमीटर उत्तर में, लुई ट्रिचर्ड शहर के पास एन1 राजमार्ग पर हुई। प्रांतीय अधिकारियों के अनुसार बस एक खड़े पर्वतीय दर्रे के पास सड़क से फिसलकर खाई में जा गिरी।

सड़क यातायात प्रबंधन निगम के प्रवक्ता साइमन जवाने ने बताया कि अधिकारियों ने मृतकों की संख्या की पुष्टि की है, लेकिन घायलों और बस में सवार कुल यात्रियों की संख्या की जांच अभी जारी है। घायल यात्रियों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति स्थिर है।

लिम्पोपो प्रांत की सरकार के बयान में कहा गया कि दुर्घटना में मारे गए यात्रियों में जिम्बाब्वे और मलावी के नागरिक शामिल होने की संभावना है, जो अपने देश लौट रहे थे। अधिकारी इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि दुर्घटना का कारण क्या था। स्थानीय सुरक्षा और आपदा प्रबंधन एजेंसियां घटना स्थल पर मौजूद हैं और बचाव कार्य जारी है। इस दुर्घटना ने क्षेत्र में सड़क सुरक्षा और पर्वतीय मार्गों पर यात्रा की जोखिमों पर फिर से सवाल उठाए हैं। अधिकारियों ने यात्रियों और परिवहन कंपनियों से सुरक्षित और सावधानीपूर्वक यात्रा करने की अपील की है।

गुजरात में बड़ा राजनीतिक मंथन: भूपेंद्र पटेल सरकार में संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल से चुनावी तैयारी तेज

(जीएनएस)। गुजरात में एक बार फिर सत्ता के गलियारों में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की सरकार में जल्द ही बड़ा फेरबदल होने की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री सोमवार को दिल्ली पहुंचे हैं, जहां वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मंत्रिपरिषद के पुनर्गठन पर गहन चर्चा करेंगे। इस बैठक में संगठन महासचिव और गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। सूत्रों के अनुसार, इस बार के फेरबदल में नए चेहरों को सरकार में शामिल किया जाएगा, जबकि कुछ मंत्रियों को उनके कार्य प्रदर्शन के आधार पर हटाया जा सकता है।

जानकारी के अनुसार, गुजरात सरकार में कुल 27 मंत्रियों की अनुमति है, लेकिन फिलहाल केवल 17 मंत्री कार्यरत हैं। इस हिसाब से 10 स्थान खाली हैं, जिन्हें इस फेरबदल के दौरान भरा जा सकता है। कुछ सीटें भविष्य की रणनीति को ध्यान में रखते हुए खाली भी रखी जा सकती हैं। दिल्ली में होने वाली बैठक में यह भी तय किया जाएगा कि किन मंत्रियों को बनाए रखना है और किन्हें बाहर किया जाएगा। यह फैसला पूरी तरह प्रदर्शन और जनता के बीच उनकी स्वीकार्यता पर आधारित होगा।

भाजपा सूत्रों का कहना है कि इस फेरबदल के पीछे दो प्रमुख कारण हैं — पहला, राज्य में जल्द होने वाले नगर निगम और स्थानीय निकाय चुनाव, और दूसरा, 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी। पार्टी चाहती है कि संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बना रहे ताकि किसी वर्ग में असंतोष न फैले। इसलिए मंत्रिमंडल में ओबीसी, पाटीदार, आदिवासी और सवर्ण समुदाय के नेताओं को संतुलित तरीके से प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

इसके अलावा, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यह भी देख रहा है कि किन मंत्रियों ने पिछले दो वर्षों में विकास कार्यों, जनसंपर्क और प्रशासनिक सुधारों में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। जिन पर लगातार शिकायतें मिल रही हैं या जिनके विभागों में ठोस काम नहीं हुआ, उन्हें इस बार बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। साथ ही, संगठन स्तर पर जो नेता लगातार मेहनत कर रहे हैं और जनता से जुड़े हुए हैं, उन्हें सरकार में जगह मिल सकती है।

भूपेंद्र पटेल के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह पहला बड़ा फेरबदल होगा। 2022 में विधानसभा चुनावों में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी, जिसके बाद भूपेंद्र पटेल को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया था। तब से अब तक उनकी टीम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि, हाल ही में भाजपा ने ओबीसी समुदाय से आने वाले नेता जगदीश विश्वकर्मा को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर यह संकेत दिया था कि पार्टी अब सामाजिक समीकरणों पर विशेष ध्यान दे रही है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा यह फेरबदल केवल सत्ता को सजाने के लिए नहीं बल्कि 2027 की नींव मजबूत करने के लिए कर रही है। गुजरात भाजपा के लिए गर्व का गढ़ रहा है और पार्टी यहां अपनी साख को और मज़बूत बनाना चाहती है। दिल्ली में आज होने वाली बैठक में यदि अंतिम सूची तय हो जाती है, तो अगले कुछ दिनों में नई मंत्री परिषद की घोषणा की जा सकती है। इससे न केवल संगठन में नई ऊर्जा आएगी बल्कि जनता के बीच यह संदेश भी जाएगा कि भाजपा लगातार आत्ममंथन कर रही है और जनहित के मुद्दों पर सतर्क है।

कोटा में 'बाहुबली' अंदाज़ में मगरमच्छ का रेस्क्यू — 8 फीट लंबा, 80 किलो वजनी अजगरनुमा जीव को कंधे पर उठाकर चंबल में छोड़ा गया

(जीएनएस)। राजस्थान के कोटा ज़िले के बंजारी गांव में शुक्रवार रात एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसे देखकर लोग दंग रह गए। जहां आमतौर पर लोग मगरमच्छ का नाम सुनते ही डर से भाग खड़े होते हैं, वहीं एक शख्स ने 'बाहुबली' की तरह 8 फीट लंबे और करीब 80 किलो वजनी मगरमच्छ को अपने कंधे पर उठाकर घर से बाहर निकाला और उसे चंबल नदी में सुरक्षित छोड़ दिया। घटना की शुरुआत बेहद सामान्य थी। लटूरलाल नामक व्यक्ति अपने परिवार के साथ घर में बैठकर हंसी-मजाक कर रहे थे कि अचानक दरवाज़े से एक बड़ा मगरमच्छ अंदर घुस आया। उसे देखते ही पूरे घर में अफरा-तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाकर बाहर भागे और तुरंत गांववालों को सूचना दी। कुछ ही देर में गांव के बाहर भीड़ जुट गई। लोगों ने तुरंत वन्यजीव प्रेमी हयात खान टाइगर को फोन किया, जो ऐसे खतरनाक रेस्क्यू के लिए जाने जाते हैं। जैसे ही हयात खान और उनकी टीम मौके पर पहुंचे, उन्होंने स्थिति का जायज़ा लिया। मगरमच्छ काफी गुस्से में था और घर के एक कोने में दुबका हुआ था। हयात ने बड़ी सावधानी से पहले उसके मुंह पर टेप लगाई ताकि वह किसी को नुकसान न पहुंचा सके। फिर टीम ने रस्सियों से उसके पैरों को बांधा और धीरे-धीरे उसे काबू में किया। लेकिन जो दृश्य इसके बाद देखने को मिला, वह फिल्मी सीन से कम नहीं था। हयात खान ने बिना किसी डर के उस 8 फीट लंबे और भारी मगरमच्छ को अपने कंधे पर उठा लिया और गांववालों की तालियों के बीच उसे बाहर लेकर निकले। गांव के लोग इस दृश्य को देखकर हैरान रह गए — किसी ने मोबाइल से वीडियो बनाया तो किसी ने जयकारे लगाए। इसके बाद हयात ने मगरमच्छ को जीप में रखकर पास की चंबल नदी के किनारे पहुंचाया और वहां उसे सुरक्षित छोड़ दिया। बताया जाता है कि हयात खान उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के रहने वाले हैं और अब तक सैकड़ों वन्य जीवों का रेस्क्यू कर चुके हैं — जिनमें सांप, अजगर, नेवला, उल्लू, बंदर और मगरमच्छ तक शामिल हैं। उन्हें उनके साहस और जीव-जंतुओं के प्रति संवेदनशीलता के लिए "टाइगर हयात" के नाम से जाना जाता है। गांववालों ने बताया कि बंजारी गांव के पास एक बड़ा तालाब है जिसमें कई मगरमच्छ रहते हैं। बारिश के मौसम में ये अक्सर बाहर निकल आते हैं, जिसके कारण ग्रामीणों को तालाब से पानी लेने में डर लगता है। यह मगरमच्छ भी उसी तालाब से रास्ता भटककर लटूरलाल के घर तक पहुंच गया था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें हयात खान अपने कंधे पर मगरमच्छ को उठाकर घर से बाहर ले जाते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो देखने के बाद लोग उन्हें "रियल लाइफ बाहुबली" और "वाइल्डलाइफ हीरो" कहकर सराह रहे हैं।

कच्छ में पति की दर्दनाक मौत, दूसरी पत्नी ने पैसों के लिए बनाया खौफनाक षड्यंत्र — ज्वलनशील तेल डालकर किया जिंदा आग के हवाले

(जीएनएस)। गुजरात के कच्छ जिले से एक ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने मानवीय रिश्तों की सीमाएं तोड़ दीं। भुज के सामत्रा गांव में शनिवार शाम एक महिला ने अपने ही पति को सिर्फ पैसे के विवाद में जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया। यह घटना न केवल क्षेत्र में बल्कि पूरे राज्य में सनसनी का कारण बनी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार, मृतक व्यक्ति की उम्र लगभग 58 वर्ष थी और उसकी यह दूसरी शादी थी। पहली पत्नी की मृत्यु के बाद डेढ़ साल पहले उसने यह दूसरी शादी की थी। मृतक के तीन बेटे हैं, जिनमें से दो विदेश में रहते हैं। मृतक का परिवार भुज में ही एक घर में रहता था, जो हाल ही में खरीदा गया था। इसी मकान की अदायगी और पैसे को लेकर दंपति के बीच पिछले कुछ दिनों से झगड़े चल रहे थे। शनिवार को शाम के करीब पांच बजे जब पति घर पर था, तब पत्नी ने पैसे मांगे, लेकिन पति ने देने से मना कर दिया। इसी बात से गुस्साई पत्नी ने गैराज से ज्वलनशील पदार्थ (संभावित रूप से केरोसिन) निकाला और पति पर डाल दिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, महिला ने माचिस की तीली जलाई और आग लगा दी। कुछ ही क्षणों में पूरा शरीर आग की लपटों में घिर गया। चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी दौड़े, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से आग बुझाई और घायल को भुज के अस्पताल पहुंचाया।

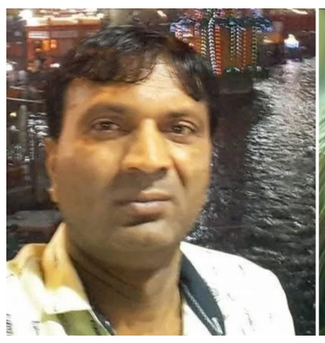

डॉक्टरों ने बताया कि मृतक के शरीर का करीब 80 प्रतिशत हिस्सा जल चुका था। कई घंटों तक जीवन बचाने की कोशिश के बावजूद रविवार शाम उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों के अनुसार, जलने की चोटें इतनी गंभीर थीं कि शरीर का कोई भी हिस्सा बचाया नहीं जा सका।

पुलिस ने घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। पूछताछ के दौरान यह भी पता चला कि आरोपी पत्नी ने शादी के कुछ समय बाद ही मृतक की पहली पत्नी के करीब 18 तोले सोने के गहने अपने कब्जे में ले लिए थे। इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच लगातार विवाद होते रहते थे। घटना के दिन भी घर में गहनों और पैसे को लेकर तीखी बहस हुई थी, जिसके बाद यह खौफनाक कदम उठाया गया।

स्थानीय लोगों ने बताया कि आरोपी महिला का व्यवहार पिछले कुछ महीनों से अजीब था। वह अक्सर पड़ोसियों से झगड़ती और पैसों की कमी की शिकायत करती थी। कई बार उसने अपने पति को धमकी भी दी थी कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह खुद या उसे नुकसान पहुंचाएगी। भुज पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल उससे पूछताछ चल रही है। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि क्या किसी और ने उसे उकसाया था या यह कदम उसने अकेले ही उठाया।

इस दर्दनाक घटना ने गांव में दहशत का माहौल बना दिया है। लोग यह सोचकर सिहर उठे हैं कि कोई पत्नी इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है कि पैसे के लिए अपने पति को जिंदा जला दे। मृतक के परिजनों ने आरोपी को सख्त सजा देने की मांग की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

भुज के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला साफ तौर पर 'पूर्व नियोजित हत्या' का प्रतीत होता है। आरोपी ने पहले से ही ज्वलनशील पदार्थ तैयार रखा था और झगड़े के दौरान मौका पाकर उसे अंजाम दिया। अधिकारी ने कहा कि यह घटना समाज के लिए चेतावनी है कि पारिवारिक विवादों को हिंसा में बदलने से पहले संवाद और संयम की आवश्यकता है, क्योंकि एक पल का क्रोध एक पूरे जीवन को समाप्त कर सकता है।

बिहार में 153 सीटों पर अकेले उतरेंगे ओम प्रकाश राजभर, बोले "हमको 4-5 सीट दे देते तो एनडीए में ही रहकर लड़ते"

(जीएनएस)। लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि उनकी पार्टी राज्य की 153 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। राजभर का कहना है कि उनकी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन बिहार के स्थानीय नेताओं ने उन्हें नजरअंदाज किया और भाजपा नेतृत्व को गुमराह किया। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा उन्हें 4-5 सीटें दे देती, तो वे अब भी एनडीए में रहकर चुनाव लड़ने को तैयार थे।

राजभर ने कहा कि वे यह चुनाव केवल सत्ता पाने के लिए नहीं बल्कि अपनी जातियों — राजभर, प्रजापति, रजवार, राजवंशी और अन्य पिछड़े समुदायों — को "पहचान" दिलाने के लिए लड़ेंगे। उन्होंने कहा, "हम हार-जीत की परवाह नहीं करते, हमारा मकसद यह है कि जिन जातियों ने दशकों से दूसरों को जिताया है, अब उन्हें भी गिना जाए, पहचाना जाए।"

राजभर ने याद दिलाया कि जब बिहार के उपचुनाव हुए थे तो बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल उनसे मदद के लिए बार-बार संपर्क कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि तब अमित शाह, जे.पी. नड्डा और विनोद तावड़े ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि जब चुनाव आएगा तो सीट बंटवारे पर बात कर ली जाएगी। लेकिन अब, जब भाजपा-जदयू गठबंधन ने सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया, तो सुभासपा को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया।

बिहार एनडीए में सोमवार को हुए सीट बंटवारे के अनुसार, भाजपा और जदयू 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को 29 सीटें, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6-6 सीटें दी गई हैं। इस घोषणा के बाद सुभासपा को किसी भी सूची में जगह नहीं मिली, जिससे राजभर नाराज़ दिखे।

राजभर के बेटे और पार्टी के महासचिव अरविंद राजभर ने शनिवार को ही पटना में पार्टी के 50 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी थी। इस सूची में मुख्य रूप से पूर्वी और उत्तरी बिहार के वे विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, जहां पूर्वांचल और पूर्वी यूपी से आए समुदायों की संख्या अधिक है।

ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बिहार में उनकी पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है और वे स्थानीय स्तर पर समाज के उपेक्षित वर्गों को साथ लेकर चुनाव मैदान में उतरेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में प्रजापति, राजभर, रजवार, राजवंशी जैसी जातियों की आबादी 20 हजार से 80 हजार तक है, लेकिन इनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व लगभग शून्य है।

राजभर ने यह भी जोड़ा कि उनकी पार्टी का संघर्ष केवल सीटों के लिए नहीं, बल्कि उन समाजों के सम्मान के लिए है, जिनके वोट से बड़ी पार्टियाँ सत्ता तक पहुंचती हैं लेकिन बाद में उन्हें भुला देती हैं। उन्होंने कहा — "बिहार के हर जिले में हमारी मौजूदगी है। हम किसी की दया से नहीं, अपने दम पर लड़ेंगे। अगर हमें एनडीए में 4-5 सीटें दे दी जातीं तो हम वहीं रहते, लेकिन अब जनता के बीच जाकर अपने हक की लड़ाई खुद लड़ेंगे।"

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राजभर का यह फैसला बिहार की राजनीति में सामाजिक समीकरणों को नया मोड़ दे सकता है। हालांकि, यह देखना दिलचस्प होगा कि सुभासपा की स्वतंत्र उपस्थिति राज्य के जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को कितना प्रभावित करती है।

वैश्विक दबाव में घरेलू शेयर बाजार फिसला, सेंसेक्स और निफ्टी में मामूली गिरावट — उतार-चढ़ाव भरे दिन में निवेशकों को फिर भी 41 हजार करोड़ रुपये का फायदा

(जीएनएस)। नई दिल्ली। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को घरेलू शेयर बाजार वैश्विक दबाव के बीच कमजोर रहा और मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। निवेशकों ने दिनभर सतर्क रुख बनाए रखा क्योंकि एशियाई और अमेरिकी बाजारों से मिले संकेत कमजोर थे। दिन के उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में सेंसेक्स 173.77 अंक यानी 0.21 प्रतिशत टूटकर 82,327.05 अंक पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी भी 58 अंक यानी 0.23 प्रतिशत गिरकर 25,227.35 अंक पर आ गया।

हालांकि बाजार की गिरावट के बावजूद निवेशकों की कुल संपत्ति में 41 हजार करोड़ रुपये से अधिक की बढ़ोतरी हुई। बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण बढ़कर 462.49 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि शुक्रवार को यह 462.08 लाख करोड़ रुपये था। इसका अर्थ यह हुआ कि गिरावट के बावजूद बाजार की व्यापकता और निवेशकों का भरोसा अभी भी कायम है।

दिनभर के कारोबार में बाजार में मिला-जुला रुख देखने को मिला। बैंकिंग और कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में खरीदारी की लहर रही, जबकि एफएमसीजी, पब्लिक सेक्टर, आईटी, ऑयल एंड गैस और मेटल सेक्टर में बिकवाली का दबाव दिखा। ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, हेल्थकेयर और टेक्नोलॉजी इंडेक्स भी लाल निशान में बंद हुए। बीएसई का मिडकैप इंडेक्स 0.18 प्रतिशत और स्मॉलकैप इंडेक्स 0.43 प्रतिशत टूटे, जिससे यह संकेत मिला कि छोटी कंपनियों में भी निवेशकों ने मुनाफावसूली की।

बीएसई में आज कुल 4,459 शेयरों में कारोबार हुआ। इनमें 1,668 कंपनियों के शेयर बढ़त में रहे, जबकि 2,622 कंपनियां गिरावट के साथ बंद हुईं। इसी तरह एनएसई में कुल 2,821 शेयरों में ट्रेडिंग हुई, जिनमें से 914 हरे निशान में और 1,907 लाल निशान में बंद हुए। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 12 में बढ़त रही, जबकि 18 शेयरों में गिरावट आई। निफ्टी के 50 शेयरों में 19 में तेजी और 31 में कमजोरी रही। आज के प्रमुख गेनर्स यानी सबसे ज्यादा लाभ देने वाले शेयरों में अदानी पोर्ट्स 2.02%, बजाज ऑटो 1.34%, बजाज फाइनेंस 1.26%, श्रीराम फाइनेंस 1.07% और इंटरग्लोब एविएशन (इंडिगो) 0.92% की मजबूती के साथ शीर्ष पर रहे। वहीं सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में टाटा मोटर्स 2.68%, विप्रो 1.44%, इंफोसिस 1.43%, हिंदुस्तान यूनिलीवर 1.43% और मैक्स हेल्थकेयर 1.13% नीचे फिसले।

सरकारी स्कूल में नॉनवेज पार्टी से मचा बवाल — मां सरस्वती की मूर्ति ढकी, परिसर में परोसा गया चिकन-मटन

(जीएनएस)। सूरत। गुजरात के सूरत जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे प्रदेश में शिक्षा संस्थानों की गरिमा और अनुशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गोडादरा स्थित एक सरकारी शिक्षण समिति स्कूल में रविवार को पूर्व छात्रों द्वारा आयोजित नॉनवेज पार्टी को लेकर भारी विवाद छिड़ गया। हैरान करने वाली बात यह रही कि इस दौरान स्कूल परिसर में स्थापित मां सरस्वती की मूर्ति को चुनरी से ढक दिया गया, जबकि उसी प्रांगण में चिकन और मटन परोसा जा रहा था।

जानकारी के अनुसार, यह पार्टी 1987 से 1991 के बीच इस स्कूल में पढ़े तेलुगू समाज के पूर्व छात्रों ने आयोजित की थी। उन्होंने रविवार को एक "गेट-टुगेदर" का कार्यक्रम रखा, जिसमें नॉनवेज भोजन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में चिकन और मटन के साथ शराब परोसे जाने की भी चर्चा है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। स्कूल के कुछ स्टाफ सदस्य, जिनमें प्रिंसिपल भी शामिल थीं, इस समारोह में मौजूद रहे।

जब स्थानीय मीडिया को इस पार्टी की खबर मिली और कैमरे लेकर पत्रकार मौके पर पहुंचे, तो अचानक अफरा-तफरी मच गई। पत्रकारों को देखते ही कई टीचर्स और स्कूल कर्मचारी जल्दबाज़ी में स्कूल परिसर से फरार हो गए। हालांकि कुछ बर्तनों और भोजन के अवशेषों से स्पष्ट हुआ कि स्कूल के भीतर नॉनवेज पार्टी आयोजित की गई थी।

स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि "सभी लोग सुबह-सुबह आए थे, लगभग सौ लोग शामिल हुए और दोपहर तक कार्यक्रम चला।" उसने यह भी बताया कि मूर्ति को चुनरी से ढकने का निर्देश आयोजकों ने खुद दिया था ताकि "कोई धार्मिक विवाद न हो।"

मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षण समिति के अध्यक्ष राजेंद्र कपाड़िया और प्रवक्ता विनोद गजेरा ने तुरंत संज्ञान लिया। उन्होंने बताया कि प्रिंसिपल से प्रारंभिक पूछताछ की गई है और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। राजेंद्र कपाड़िया ने कहा — "सोमवार को समिति की विशेष बैठक बुलाई गई है, जिसमें पूरे प्रकरण की जांच कर जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।"

इस घटना ने शिक्षा जगत में आक्रोश पैदा कर दिया है। स्थानीय अभिभावक संघ और सामाजिक संगठनों ने कहा कि स्कूलों में जहां मां सरस्वती की पूजा होती है, वहां नॉनवेज पार्टी करना शैक्षिक संस्थान की पवित्रता का अपमान है। कुछ संगठनों ने स्कूल प्रशासन पर भी कार्रवाई की मांग की है।

यह पहली बार नहीं है जब किसी सरकारी स्कूल में इस तरह का मामला सामने आया हो। कुछ महीने पहले बिहार के भभुआ जिले में 11 शिक्षकों ने स्कूल परिसर में चिकन पार्टी आयोजित की थी, जिसका वीडियो वायरल हो गया था। उस घटना में जांच के बाद सभी शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया था।

गुजरात की इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि सरकारी स्कूलों में अनुशासन और मर्यादा की सीमाएँ कितनी शिथिल हो चुकी हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि स्कूलों को धार्मिक और सामाजिक सम्मान का केंद्र माना जाता है, लेकिन जब वहां के जिम्मेदार ही उसका उल्लंघन करें, तो यह आने वाली पीढ़ी के लिए खतरनाक संदेश है। अब सबकी नजरें सोमवार की बैठक पर टिकी हैं, जिसमें यह तय होगा कि सूरत के इस सरकारी स्कूल में मां सरस्वती की मूर्ति के सामने नॉनवेज परोसने के इस "असंवेदनशील कृत्य" पर प्रशासन आखिर क्या सख्त कदम उठाता है।

इन्वेस्ट यूपी का पुनर्गठन: निवेशक केंद्रित, विशेषज्ञता आधारित और औद्योगिक विकास में नई ऊँचाई

(जीएनएस)। लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को इन्वेस्ट यूपी शासी निकाय की पहली बैठक में संस्था के पुनर्गठन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस पुनर्गठन का उद्देश्य इन्वेस्ट यूपी को अधिक कार्यकुशल, विशेषज्ञता आधारित और निवेशक केंद्रित संस्था बनाना है। नए ढांचे के तहत टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल एवं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्विस सेक्टर के लिए अलग-अलग विशेषज्ञ सेल बनाए जाएंगे। इसके साथ ही मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली में सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफिस स्थापित किए जाएंगे, ताकि घरेलू और विदेशी निवेशकों से सीधा संवाद स्थापित किया जा सके।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि इन्वेस्ट यूपी को एक 'एकल निवेश सुविधा एजेंसी' के रूप में सशक्त किया जाएगा। यह एजेंसी न केवल निवेश आकर्षित करेगी, बल्कि परियोजनाओं के क्रियान्वयन तक उनकी निगरानी भी करेगी। बैठक में 11 महाप्रबंधक और सहायक महाप्रबंधक पदों को स्वीकृति दी गई, जबकि दो पीसीएस अधिकारियों को संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया। साथ ही भूमि बैंक प्रकोष्ठ भी गठित किया जाएगा, जिसमें दो पीसीएस अधिकारी तैनात रहेंगे।

बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि उत्तर प्रदेश ने पिछले कुछ वर्षों में औद्योगिक विकास में उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2024-25 में लगभग 4,000 नई फैक्ट्रियां स्थापित हुईं, जिससे कुल संख्या 27,000 तक पहुंच गई। मुख्यमंत्री ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म' मंत्र के सफल क्रियान्वयन का परिणाम बताया, जिससे राज्य का औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र और मजबूत हुआ है। निवेश मित्र पोर्टल 3.0 के माध्यम से औद्योगिक निवेश प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नई सुविधाएँ जोड़ी जा रही हैं। इसमें सिंगल साइन-ऑन, डायनेमिक एप्लीकेशन सिस्टम, एआई चैटबॉट, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन और डिजिटल मॉनिटरिंग जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इससे आवेदन, स्वीकृति और प्रोत्साहन प्रक्रिया में समय 30 प्रतिशत और दस्तावेजी औपचारिकताओं में 50 प्रतिशत तक कमी आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक निवेश अब सिर्फ नीतिगत प्रतिबद्धता नहीं, बल्कि "ग्राउंड लेवल डिलीवरी" का उदाहरण बन चुका है।

योगी आदित्यनाथ ने वैश्विक निवेशकों से सक्रिय संवाद बनाए रखने के निर्देश दिए। इसमें जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, फ्रांस, रूस, ताइवान, सिंगापुर और खाड़ी देशों के निवेशक शामिल हैं। उन्होंने 'सेफ सिटी' की तर्ज पर 'सेफ इंडस्ट्री' की अवधारणा लागू करने के निर्देश दिए, जिसमें औद्योगिक क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मंडलायुक्त और जिलाधिकारी नियमित रूप से निवेशकों से संवाद करें और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें। बैठक में निवेश मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी', नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा, एमएसएमई मंत्री राकेश सचान समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस पुनर्गठन और नई रणनीति से उत्तर प्रदेश में निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण बनेगा, औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और राज्य की आर्थिक प्रतिस्पर्धा और मजबूती के नए आयाम स्थापित होंगे।

आरपीएफ रांची की सतर्कता से मानव तस्करी की बड़ी साजिश नाकाम — तीन मासूम बच्चे सुरक्षित बचाए गए

(जीएनएस)। रांची। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) रांची ने अपनी सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से मानव तस्करी की एक बड़ी कोशिश को विफल कर दिया। यह घटना रविवार देर शाम रांची रेलवे स्टेशन की है, जहां आरपीएफ, एसआईबी और नन्हे फरिश्ते नामक संस्था की संयुक्त टीम ने तीन नाबालिग बच्चों को तस्करों के चंगुल से आज़ाद कराया। यह पूरी कार्रवाई आरपीएफ कमांडेंट पवन कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने रांची रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 01A पर कड़ी निगरानी रखी। उसी दौरान लोहरदगा–रांची मेमू पैसेंजर ट्रेन से एक संदिग्ध व्यक्ति तीन बच्चों के साथ उतरा। संदिग्ध के हावभाव देखकर टीम ने तुरंत कार्रवाई की और उसे पकड़ लिया। प्रारंभिक पूछताछ में वह बच्चों के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। इसके बाद टीम ने सभी को आरपीएफ पोस्ट लाकर विस्तृत पूछताछ की।

पूछताछ में खुलासा हुआ कि तीनों बच्चे जिला गुमला के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति आयुष असुर उन्हें "काम दिलाने" के बहाने लोहरदगा से रांची लेकर आया था। वहां से उन्हें जगतपाल उरांव नामक व्यक्ति के हवाले किया गया, जो बच्चों को आगे अगरतला (त्रिपुरा) ले जाने की फिराक में था। आरपीएफ ने तुरंत जाल बिछाकर जगतपाल उरांव (आयु 33 वर्ष, निवासी गुमला) को गिरफ्तार कर लिया।

आरोपी ने पूछताछ में अपना अपराध कबूल करते हुए बताया कि उसे तीनों बच्चों को रांची तक लाने के लिए 5000 की रकम दी गई थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि वह पहले भी ऐसी गतिविधियों में शामिल रहा है। आरपीएफ ने आरोपी से मिले दस्तावेज़, मोबाइल और कुछ अन्य सामान जब्त कर लिया है।

बचाए गए तीनों नाबालिगों को सुरक्षित संरक्षण में लिया गया और बाद में आरोपी सहित उन्हें एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU), रांची को आगे की कार्रवाई के लिए सौंप दिया गया।

आरपीएफ कमांडेंट पवन कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा, "मानव तस्करी एक जघन्य सामाजिक अपराध है। रेलवे पुलिस ऐसे मामलों को लेकर पूरी तरह सजग और प्रतिबद्ध है। हमारी टीमें बच्चों की सुरक्षा के लिए हर स्तर पर निगरानी रखती हैं।" उन्होंने बताया कि यह सफलता तीनों इकाइयों — आरपीएफ, एसआईबी और नन्हे फरिश्ते — के बीच उत्कृष्ट समन्वय का परिणाम है।

इस अभियान में एसआई सूरज पांडे, एसआई अश्विनी कुमार, इंस्पेक्टर एस.एन. प्रसाद, कांस्टेबल संजय यादव, प्रदीप कुमार, रंजीत कुमार, एसआई सुनीता तिर्की, सुचिता, और देवमणि जैसी कई अधिकारियों और जवानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीनों बच्चों को अब सुरक्षित रूप से सरकारी संरक्षण गृह में रखा गया है। वहीं, आरोपी पर मानव तस्करी से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। इस सफल कार्रवाई से एक बार फिर यह साबित हुआ है कि रेलवे पुलिस केवल यात्रियों की सुरक्षा ही नहीं बल्कि समाज के सबसे कमजोर वर्गों—बच्चों और महिलाओं—की रक्षा में भी अग्रणी भूमिका निभा रही है।